माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2022–23 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. मुझे वर्तमान सरकार का पाँचवां बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। गत् चार वर्षों में हमारी सरकार ने अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद जन आकाँक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रगति की अभूतपूर्व गाथा लिखी है। आज हमारा प्रदेश विकास के मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। गत् चार वर्षों में हमारी सरकार ने विकास प्रक्रिया का लाभ प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुँचाया है। हमारी सरकार ने 'उज्जवला', 'मुख्यमन्त्री गृहिणी सुविधा योजना', 'प्रधानमन्त्री किसान सम्मान योजना', 'आयुष्मान भारत', 'हिमकेयर', 'सहारा', 'जनमंच' तथा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से चलाई जा रही अनेक योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा का प्रयास किया है।

3. हम माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सूत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य पूरे प्रदेश का एक समान विकास करना और हिमाचल वासियों को उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने का समुचित अवसर प्रदान करना है। हमारी सरकार के इन प्रयासों में केन्द्र सरकार का भरपूर सहयोग रहा है। मैं माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह के लिए दिल की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूँ।

सेवा और सिद्धि के,
चार साल समृद्धि के।

4. हम जनता के सेवक हैं और जन सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे सभी संकल्प प्रदेश हित से प्रेरित हैं। हमारे इरादे बड़े हैं और हमारी सारी शक्ति इन पावन संकल्पों को सिद्ध करने में लगी है। हमें विश्वास है कि दिसम्बर, 2017 की तरह प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें फिर से मिलेगा और प्रदेश के विकास का क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा।

मिट्टी से कुछ ख्वाब उगाने आया हूँ,
मैं धरती का गीत सुनाने आया हूँ।
चार दीये तेरी दहलीज़ पे हैं रौशन,
एक दीया मैं और जलाने आया हूँ।

5. कोरोना की प्रथम लहर के समय प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव देखा गया परन्तु हमने तमाम कठिनाईयों और बाधाओं को पार करते हुए इस समस्या का सामना किया। यही कारण है कि कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के आने तक हमने स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ किया और हम इस महामारी से निपटने में सफल हो पाए। महामारी से पूर्व जहाँ प्रदेश में केवल 2 ऑक्सीज़न संयन्त्र थे उनकी संख्या बढ़कर आज 48 हो गई है। इसी प्रकार आज प्रदेश में उप–स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक 5 हज़ार से अधिक Oxygen Concentrators उपलब्ध हैं। इस महामारी ने व्यक्तिगत स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सोच, समझ और कार्यशैली में दीर्घकालिक परिवर्तन किये हैं जो अभी भी जारी हैं। प्रदेश वासियों ने इस परीक्षा के समय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। इस महामारी में हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। इस विकट काल में हमारी सरकार प्रदेश वासियों के साथ खड़ी है। हमने इस महामारी के समय जीवन को बचाने के प्रयास तो किये ही साथ ही आजीविका को भी बनाये रखा।

6. हमारी सरकार का जनता के प्रति समर्पण और घोषित लक्ष्यों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता इस बात से प्रकट होती है कि हिमाचल प्रदेश कोविड टीकाकरण में पहली और

दूसरी डोज़ लगाने में देश में पहला राज्य बना। हमने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को भी उत्कृष्टता से प्रारम्भ किया है और वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज़ भी पूरी सफलता के साथ लगाई जा रही है। सितम्बर, 2021 में अपने वर्चुअल सम्बोधन में माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश को **'चैम्पियन'** राज्य की उपमा देना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। केन्द्र सरकार द्वारा समय पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए मैं माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर उद्यमियों ने अतिरिक्त निवेश किया और आज हिमाचल प्रदेश में निर्मित मास्क, PPE किट और अन्य सामग्री दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि रूस में निर्मित **'स्पुतनिक'** कोविड वैक्सीन का व्यवसायिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। यह सफलता हमारी सरकार की निवेशक हितैषी तथा ease of doing business को बढ़ाने वाली नीतियों का परिणाम है। हमारा काम करने का तरीका यह हैः–

मेहनत इतनी खामोशी से करो,
कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे।

7. कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार का हाथ पकड़ा एवम् हमें भरपूर सहयोग दिया। 2021–22 में भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पूँजीगत निवेश के लिए दी। इस सहायता का उपयोग महत्वपूर्ण निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। चिन्हित कार्यों को अगले 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। 2022–23 के केन्द्रीय बजट में इस आबंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पूँजीगत कार्यों में अतिरिक्त निवेश के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति तो मिली ही है साथ ही रोज़गार के नए अवसर सृजित हुए हैं। राज्य सरकार श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति इस सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

8. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चित्ता के चलते आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान रहे हैं तथा मुद्रास्फिति में बढ़ौतरी हुई है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने 'प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना', 'आत्मनिर्भर भारत', 'मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजना' के अन्तर्गत तथा 'Building and Construction Workers Welfare Board' के माध्यम से कमज़ोर वर्गों एवम् व्यवसायियों के लिए खुले दिल से सहायता प्रदान की जिसके कारण महामारी के दुष्प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सका।

9. भारत सरकार के प्रयत्नों के चलते 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि 2020-21 के दौरान 7.3 प्रतिशत की गिरावट (negative growth) दर्ज की गई थी। 2021-22 में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 11.8 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। देश की अर्थव्यवस्था की यह त्वरित एवम् प्रभावी 'V Shape' रिकवरी का श्रेय हमारे ऊर्जावान प्रधानमन्त्री परमश्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी के अभिनव और साहसिक नेतृत्व को जाता है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था

10. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2021-22 के दौरान 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रतिकूल परिस्थितियों में पिछले वर्ष आई गिरावट के बावजूद इतनी वृद्धि हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलु उत्पाद(GSDP) 1 लाख 75 हजार 173 करोड़ रुपये रहेगा। अग्रिम अनुमानों के अनुसार ही 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 1 हजार 854 रुपये आँकी गई है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय से 51 हजार 528 रुपये अधिक है।

विकास बजट

11. अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से बजट के बदले स्वरूप के निरन्तरीकरण में भारत सरकार द्वारा सभी

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत एक Single Nodal Agency Account (SNA) खोलने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता राशि राज्य अँशदान सहित अब बहुत ही कम समय में कार्यकारी विभागों के बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में केन्द्र सरकार की समस्त 91 योजनाओं को इस व्यवस्था के अधीन लाया गया है। 30 राज्य एवम् DBT योजनाओं को भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत 2022–23 में लाया जाएगा।

12. 2022–23 के लिए 12 हजार 921 करोड़ रुपये के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9 हजार 524 करोड़ रुपये के प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2 हजार 400 करोड़ रुपये तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 856 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं।

13. वर्तमान सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं की DPRs बनाने तथा उनको नाबार्ड के Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) के अन्तर्गत स्वीकृतियों में तेज़ी लाने के लिए विशेष प्रयास किये गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूँगा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 3 हजार 200 करोड़ रुपये की लागत से 779 योजनायें नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गईं थी। जबकि हमारी वर्तमान सरकार द्वारा प्रथम 4 वर्षों के कार्यकाल में ही 3 हजार 452 करोड़ रुपये की लागत की 826 योजनायें नाबार्ड से स्वीकृत करवा ली गई हैं।

14. हाल ही में माननीय विधायकों के साथ दो दिवसीय बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में

माननीय विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः–

- नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा जो कि 2017–18 की सीमा से लगभग दोगुना है।
- नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं में 2022–23 से माननीय विधायक 'रोपवेज़ परियोजनाएं' सम्मिलित कर सकेंगे।
- 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' से माननीय विधायक शहीदों के सम्मान में 'द्वार' इत्यादि बनाने की अनुशंसा कर सकेंगे।
- 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के अन्तर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 1 करोड़ 80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इस वृद्धि के साथ ही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस निधि में कुल 90 लाख रुपये प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी जो कि लगभग दोगुनी है।
- 'विधायक ऐच्छिक निधि' को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र कर दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण करवाना चाहूँगा कि जब मेरी सरकार आई थी तो यह राशि 5 लाख रुपये थी।

लहरों की खामोशी को,
समन्दर की बेबसी न समझ।
जितनी गहराई अन्दर है,
बाहर उतना तूफान बाकी है।।

गृहिणी सुविधा योजना/ खाद्य सुरक्षा

15. अध्यक्ष महोदय, हमने 'उज्जवला योजना' का विस्तार करते हुए 'गृहिणी सुविधा योजना' शुरु की जिसके तहत हमने हिमाचल को धुआँ रहित प्रदेश घोषित कर दिया

है। मैं घोषणा करता हूँ कि इन दोनों योजनाओं को 2022–23 में भी जारी रखा जाएगा तथा इनका और विस्तार किया जाएगा। मैं यह भी सहर्ष घोषणा करता हूँ कि दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को कनेक्शन के समय उपलब्ध करवाए गए मुफ्त सिलेंडर सहित तीन निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाये जाएंगे।

उपभोक्ताओं को इनसे निम्न लाभ प्राप्त होंगेः–

- नये कनेक्शन पर एक वर्ष में तीन निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे।
- जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ एक सिलेंडर लिया हो उन्हें दो अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे।
- जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ दो सिलेंडर लिया हो उन्हें एक अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे।

मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि 2022–23 में इसके लिए 70 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 50 करोड़ रुपये अधिक हैं।

माताओं, बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट,
‘गृहिणी सुविधा योजना’ खुशी लेकर आई है।
हिमाचल बना देश का पहला धुँआ मुक्त प्रदेश,
जन सहयोग से हमने यह मन्ज़िल पाई है।।

16. प्रदेश में वर्तमान में अनाज़ की बिक्री के लिए कोई भी विशिष्ट मण्डी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में पैदा होने वाले अनाज़ को पड़ोसी राज्यों में बिक्री के लिए भेजने में मुश्किलें आईं। प्रदेश में आगामी रबी सीज़न में 11 स्थानों पर अनाज़ की खरीद शुरु कर दी जाएगी जिसमें खरीद सम्बन्धी सभी सुविधायें जैसे – ग्रेडिंग व सफाई के लिए मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीनें, covered तथा खुला नीलामी मंच, क्रेटस, टैंट, पार्किंग, किसानों को बैठने के लिए उचित स्थान आदि उपलब्ध करवाई जाएंगी। 15 करोड़ रुपये की लागत से 4 नई अनाज़ मण्डियां

रामपुर (ऊना), मजारी (बिलासपुर), रियाली एवम् मिलवा (काँगड़ा) में स्थापित की जाएंगी।

कृषि

17. अध्यक्ष महोदय, कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने बहुत सम्बल प्रदान किया है। वर्तमान वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान है जो कि बहुत उत्साहवर्धक है। पिछले बजट को प्रस्तुत करते समय मैंने कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों के लिए Expert Group के गठन की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार ने प्रो० रमेश चन्द जोकि नीति आयोग के सदस्य हैं, की अध्यक्षता में इस Expert Group का गठन किया। Expert Group द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। इसके अध्ययन के बाद सम्बन्धित विभाग रिपोर्ट में दिये गए सुझावों पर शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे।

18. 2018–19 का बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान (PK3Y)' योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। इस योजना के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। माननीय प्रधानमन्त्री जी ने 16 दिसम्बर, 2022 को गुजरात में प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए हिमाचल का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक कृषि अपनाने का आह्वान किया है। 2022–23 के केन्द्रीय बजट में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 15 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश chemical मुक्त प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गए हैंः–

- 2022–23 के अन्त तक कुल 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा।
- प्रदेश की सभी 3 हजार 615 ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक कृषि का एक–एक मॉडल विकसित किया जाएगा, जिस से आस–पास के किसानों को

प्रशिक्षित करने व प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।

- प्रदेश में कम से कम 100 गाँवों को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्राकृतिक कृषि गाँव के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
- प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों को पँजीकृत किया जाएगा तथा उनमें से श्रेष्ठ 50 हजार किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि की पूर्ण सूचना व आँकड़ों के साथ एक Dynamic Online Web Portal विकसित किया जाएगा।
- प्रदेश की 10 मण्डियों में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्थान उपलब्ध करवाये जाएंगे तथा 2 स्थानों पर प्राकृतिक कृषि के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष मण्डी स्थापित की जाएगी।
- प्राकृतिक कृषि के उत्पादों की बिक्री के लिए देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश में चुने हुए स्थानों पर बिक्री केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय मैं किसान भाईयों का आह्वान करते हुये कहना चाहूँगाः–

आओ मिलकर मुट्ठी बाँधें,
धरती का श्रृंगार करें।
खेतों में हरियाली रोपें,
समृद्धि का संचार करें।।

19. गत् वर्ष हमारी सरकार ने पहली बार कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों को एक निश्चित शोध ग्रांट देने की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमन्त्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवम् स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में

संशोधन किया जाएगा तथा शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा।

20. पराला मण्डी को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित किया जा रहा है। फलों और सब्जियों के भण्डारण की सुविधाओं में और अधिक बेहतरी के लिए इस मण्डी में 60 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता का एक नया Cold Store स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 1 हजार 500 मीट्रिक टन क्षमता का Freezing Chamber, 10 मीट्रिक टन प्रति घण्टा क्षमता की Grading Packing Line और एक मीट्रिक टन प्रति घण्टा क्षमता की Individually Quick Freezing (IQF) लाईन स्थापित की जाएगी।

21. किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले इस के लिए अगले वित्तीय वर्ष में JICA चरण–2 परियोजना के तहत प्रदेश के 13 मार्केट यार्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा जिस पर 31 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

22. पिछले वर्ष बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए मैंने प्रदेश में एक फूल मण्डी की स्थापना करने की घोषणा की थी जिसे परवाणू में स्थापित कर दिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में एक और फूल मण्डी स्थापित करने की घोषणा करता हूँ जिस पर 3 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

23. हमारी सरकार ने हींग और केसर की खेती प्रायोगिक तौर पर शुरू की है जिसके प्रारम्भिक परिणाम उत्साहवर्धक हैं। अब प्रदेश में दालचीनी एवम् मौंक फ्रूट की खेती को Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), पालमपुर के सहयोग से पायलट आधार पर आरम्भ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती की सम्भावनाओं को भी तलाशा जाएगा।

24. प्रदेश में मक्की और गेहूँ की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा प्रदेश की अपनी पहाड़ी किस्मों के संवर्धन के लिए मैं बीज उपदान के वर्तमान आबंटन को

5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्तम बीज उपलब्ध करवाने के लिए मैं 3 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की घोषणा करता हूँ।

25. मैं प्रदेश में पहाड़ी मक्की की किस्मों को उपभोक्ताओं तक Value Addition एवं उचित Branding करके पहुँचाने की व्यवस्था करने के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ।

26. कृषि क्षेत्र में किसानों को बाजार से सीधा जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन किया जा रहा है। ये FPOs छोटे और सीमान्त किसानों को अपनी उपज बेहतर दाम पर बेचने के लिए एक सशक्त माध्यम हैं। अगले वर्ष 20 और FPOs गठित किये जाएंगे जिन में से 10 FPOs केवल प्राकृतिक कृषि पर आधारित होंगे। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग भी प्रत्येक विकास खण्ड में एक FPO स्थापित करेगा। सहकारिता विभाग इन FPOs को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

कृषि क्षेत्र के लिए 2022–23 में 583 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बागवानी

27. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देश भर में Fruit Bowl के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है। इस क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक बागवानी नीति तैयार की जाएगी एवम् निम्न बिन्दुओं पर पहल की जाएगीः–

- फूलों की खेती का विस्तार करने के लिए आर्किड और सजावटी पौधों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पुष्प क्रान्ति योजना के अन्तर्गत 11 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

- Bee-Flora के लिए विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और भारतीय मधुमक्खियों की

किस्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे।

- शिटाके और ढींगरी आदि मशरूम की किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तथा मशरूम Processing & Canning के लिए 3 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।
- जामुन और मेवों की खेती के लिए क्लस्टर बनाये जाएंगे।
- High Density किस्मों का पौधरोपण और इम्युनिटी बूस्टर वाली फसलों की शुरुआत की जाएगी।

28. हिमाचल प्रदेश की जनता स्वर्गीय श्री सत्यानन्द स्टोक्स की ऋणी है जिनके प्रयास एवम् मार्गदर्शन से 1916 में प्रदेश में सेब का उत्पादन आरम्भ हुआ तथा प्रदेश की बागवानी को एक नई दिशा एवं गति प्राप्त हुई। बागवानी क्षेत्र का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। श्री सत्यानन्द स्टोक्स का देहावसान हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनके व्यक्तित्व एवम् योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुये मैं घोषणा करता हूँ कि उनकी कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़ थानाधार व आस–पास के क्षेत्र को 'सत्यानन्द स्टोक्स ट्रेल' बनाया जाएगा। इसका बहुआयामी स्वरूप बागवानी, पर्यटन एवम् भाषा एवं संस्कृति विभागों के समन्वय से विकसित किया जाएगा।

29. विभिन्न स्थानों पर Processing and Canning Units के अतिरिक्त CA Store स्थापित किये जा रहे हैं। 58 करोड़ रुपये की लागत से चच्योट, रिकांगपिओ, झाबोंग और चम्बा में CA Stores का निर्माण 2022–23 में आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रोहड़ू, गुम्मा, जड़ोल टिक्कर, टूटूपानी तथा भुन्तर में बन रहे CA स्टोर तथा Grading & Packaging Houses का इसी वर्ष लोकार्पण कर दिया जाएगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 75 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

30. 2022–23 के दौरान 91 करोड़ रुपये की लागत से पराला में बन रहे Fruit Processing Unit में उत्पादन आरम्भ कर दिया जाएगा तथा परवाणु और जड़ोल में स्थित Fruit Processing Unit का 17 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही पांवटा साहिब, कांगनी तथा शाट में बन रहे मार्केट यार्डस को सितम्बर, 2022 तक किसानों एवं बागवानों को समर्पित कर दिया जाएगा। परवाणु में बन रहे मार्केट यार्ड को भी मार्च, 2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इन पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

31. बागवानी क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। 2022–23 में लगभग 9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इस पर 198 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

32. 'बागवानी विकास परियोजना' के सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत शिलारु एवं पालमपुर में दो Centre of Excellence स्थापित किये जाएंगे जिसके लिए 18 करोड़ रुपये के प्रावधान को मैं प्रस्तावित करता हूँ।

बागवानी क्षेत्र के लिए 2022–23 में 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन/ गौ–संरक्षण

33. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के लिए गौवँश का संरक्षण आस्था का विषय है। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान वर्तमान सरकार के मन्त्रिमण्डल की पहली बैठक की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसमें हमने गौवँश सेवा का संकल्प लिया था। हमने न केवल विभागीय स्तर पर बड़ी cow sanctuaries और गौशालाओं की स्थापना की है अपितु निजी भागीदारी से भी उत्कृष्ट गौ–सदनों को प्रोत्साहन दिया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में बेसहारा गायें सड़कों पर दिखाई देती थीं। हमारे प्रयासों के चलते गौशालाओं तथा cow sanctuaries में गौवँश की संख्या

6 हजार से बढ़कर 20 हजार हो गई है। हमें विश्वास है कि सरकार के प्रयासों तथा गैर–सरकारी एवं समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से हम पूरे प्रदेश में बेसहारा गौवँश की सेवा सुनिश्चित कर देंगे। मैं सभी समाजसेवियों का इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रदेश वासियों का भी आह्वान करता हूँ कि वे गौवँश के प्रति अपने कर्त्तव्य को निभाएं। इस सन्दर्भ मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सरकार वर्तमान कानूनों में कड़े प्रावधान करेगी तथा यदि आवश्यकता हुई तो नया कानून भी बनाया जाएगा।

34. मैं 2022–23 में पाँच बड़ी Cow Sanctuaries एवम् गौ–सदनों की स्थापना तथा हिमाचली पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट फार्म स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

35. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुये निजी गौ–सदनों में आश्रित गौवँश के लिए दिये जाने वाले अनुदान को 500 रुपये प्रति गौवँश प्रतिमाह से बढ़ाकर 700 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि इस व्यवस्था को अब **"गोपाल"** के नाम से जाना जाएगा। सरकारी क्षेत्र के गौ–सदनों के अनुदान में आवश्यकतानुसार समुचित वृद्धि की जाएगी।

जब गाय नहीं होंगी तो गोपाल कहाँ होंगे,
इस दुनिया में हम सब खुशहाल कहाँ होंगे।

36. 2022–23 में डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिए दत्तनगर तथा चक्कर (मण्डी) में प्रतिदिन 50 हजार लीटर क्षमता के दो Milk Processing Plants शुरु किये जाएंगे।

37. अध्यक्ष महोदय, विगत 4 वर्षों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से मैंने दूध खरीद मूल्य में 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ौतरी की है। 2022–23 के लिए भी मैं इसमें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

38. अध्यक्ष महोदय, पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार 44 Mobile Veterinary Ambulances चलाई जाएंगी जिन पर 7 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। पशु पालकों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी।

39. पशु पालकों की आय बढ़ाने के लिए 'Rural Backyard Sheep Development Scheme' के अन्तर्गत 2 हजार भेड़ ईकाइयाँ स्थापित की जाएंगी जिस पर 12 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

40. दस करोड़ रुपये की लागत से 'राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम' चरण-3 के अन्तर्गत 5 लाख गाय व भैंसों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये की लागत से Sex Sorted Semen पर आधारित कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाएगी।

41. 'मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना' के तहत कार्य कर रहे कई ग्राम पंचायत Veterinary Assistants, Veterinary Pharmacist के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हो गये हैं। पात्र पशुपालन सहायकों को Pharmacist के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार स्कीम अथवा सम्बन्धित नियमों में बदलाव किया जाएगा।

पशुपालन क्षेत्र के लिए 2022-23 में 469 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य पालन

42. अध्यक्ष महोदय, मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता एवं सम्भावनाओं को देखते हुये 2022-23 में 120 नई ट्राउट इकाईयों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में Biofloc मत्स्य पालन इकाई, ट्राउट हैचरी, मछली फीड मिल और बर्फ संयन्त्र स्थापित किये जाएंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में 20 हैक्टेयर में नये मत्स्य पालन तालाबों का निर्माण किया जाएगा।

43. 2022–23 के दौरान मछुआरों को आईस बॉक्स सहित 20 थ्री–व्हीलर और 80 मोटर साईकिल, 200 नावें और जाल अनुदान पर प्रदान किये जाएंगे। पुरुषों के लिए यह अनुदान राशि कुल लागत का 40 प्रतिशत तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 60 प्रतिशत होगी।

44. मत्स्य पालन क्षेत्र में 2022–23 में ग्रामीण क्षेत्र के 500 युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन

45. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पैंशन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के जीवन यापन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि हमारी प्रथम मन्त्रिमण्डल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसमें बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली बुढ़ापा पैंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया था जिसका सीधा लाभ 3 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। पात्र व्यक्तियों को वर्तमान में 1 हजार 500 रुपये प्रति माह पैंशन प्रदान की जा रही है।

46. उपरोक्त के अतिरिक्त गत् 4 वर्षों के दौरान हमने सामाजिक सुरक्षा पैंशन की दरों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ौतरी करते हुए निम्नलिखित लाभ दिये हैं:–

- विधवाओं, एकल नारी तथा 70 वर्ष से नीचे वृद्धजनों को मिलने वाली 700 रुपये प्रतिमाह पैंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह।
- 70 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों तथा 70 प्रतिशत अपंगता वाले दिव्यांगजनों को मिलने वाली पैंशन को 1,100 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 हजार 500 प्रतिमाह।
- 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपये प्रतिमाह।

- कुष्ठ रोगी एवम् ट्रांसजैंडर को मिलने वाली 700 रुपये प्रतिमाह पैंशन को बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह।

2017 तक प्रदेश में सवा चार लाख व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पैंशन ले रहे थे जिन पर लगभग 450 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही थी। हमने अपने सरकार के चार साल के कार्यकाल के अन्दर ही 2 लाख 20 हजार से अधिक नये पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन स्वीकृत की है।

47. हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 6 लाख 35 हजार लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40 हजार अतिरिक्त पात्र आवेदकों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी।

48. अभी हाल ही में हमने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा, जो 2014 में 35 हजार रुपये निर्धारित की थी, को बढ़ाकर 50 हजार वार्षिक कर दिया है। इस निर्णय से 60 हजार से अधिक अतिरिक्त लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा/एकल नारी और दिव्यांगजन पैंशन का लाभ मिलेगा।

49. मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए मैं, मेरी सरकार के दृष्टिपत्र में किये गए वादे को पूरा करते हुए, सभी के लिए बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष करने की घोषणा करता हूँ।

जहाँ सजदा हो बुजुर्गों का,
वहाँ की तहजीब अच्छी है।
जहाँ लांघे न कोई मर्यादा,
वो दहलीज अच्छी है।।

50. मैं 60 वर्ष से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों, कुष्ठ रोगियों एवं ट्रांसजैंडर को दी जा रही पैंशन 850 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रति माह, विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं व एकल नारियों को दी जा रही पैंशन एक हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1 हजार 150 रुपये प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों एवं 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पैंशन 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 हजार 700 रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

51. अध्यक्ष महोदय, हमने सामाजिक सुरक्षा पैंशन की परिधि को संख्या एवम् परिव्यय दोनों की ही दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया है। परिणामस्वरूप 2022–23 में 7 लाख 50 हजार से अधिक व्यक्ति इस योजना से लाभ उठा पाएंगे एवम् 2017–18 में इस पर होने वाले 450 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 2022–23 में 1 हजार 300 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इस प्रकार हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में ही सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के परिव्ययों में तीन गुणा वृद्धि की है।

अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए इस बजट में घोषित लाभों का सार निम्न हैः–

पैंशन में वृद्धि

- ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 150 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

लाभार्थियों का विस्तार

- 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलायें बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन का लाभ पाने की पात्र होंगी।
- 60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुष बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन का लाभ पाने के पात्र होंगे।

सबकी दुआओं को दिल में उतारना है,
हमको तो हर घर का चूल्हा सँवारना है।

52. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश एवं राष्ट्र के निर्माण में हमारी माताओं और बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण एवम् Gender Equality के लिए तत्परता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। एक नई पहल करते हुये 2022–23 में एक अलग से Gender Budget Statement सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस Statement में ऐसी सभी योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध है। इस statement के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा तथा उनमें महिलाओं से संवाद के पश्चात् आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी। महिला एवं बाल विकास एवं कमज़ोर वर्गों का कल्याण

53. मैंने पिछले बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय सदन को यह सूचित किया था कि हमारी सरकार बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, कुपोषण एवं एनीमिया को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है, तथा हम नीति आयोग के साथ मिलकर इस गम्भीर विषय पर एक स्टडी करवाएंगे जिसके आधार पर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा।

54. प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में डॉ0 वी. के. पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया व एक्शन प्लान बना लिया है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई **“मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना”**

प्रारम्भ की जाएगी। यह योजना सात स्तम्भों पर स्थापित होगीः–

- बच्चों की शारीरिक वृद्धि में दो मूल बीमारियों डायरिया तथा निमोनिया का शीघ्र पता लगाना और उसका सही उपचार करना।
- कम वज़न वाले नवजात शिशु एवं कुपोषण से सम्भावित प्रभावित होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की गहन निगरानी व सतत् समीक्षा।
- पूरक पोषाहार के लिए उपयुक्त प्रोटीन युक्त आहार।
- बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं में एनीमिया के उपचार के लिए विशेष प्रयास।
- उच्च रक्तचाप और एनीमिया से पीड़ित गर्भवती व धात्री (दूध पिलाने वाली मातायें) की समय रहते पहचान और उपचार।
- कुपोषित बच्चों का सही उपचार।
- IEC और Monitoring पर विशेष बल।

55. यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के परस्पर समन्वय तथा प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के तालमेल से चलाई जाएगी। यह अति आवश्यक है कि सभी विभागों के मध्य सम्पूर्ण समन्वय स्थापित हो और इनके कर्मियों के मध्य नियमित संवाद हो जिसके आधार पर आवश्यक सूचकाँकों का चयन हो। इसके लिए सुदृढ़ इंटर फेस पोर्टेबिलिटी (Interface Portability) और डाटा इंटर–ऑपरेबिलिटी (Data Inter-operability) सुनिश्चित की जाएगी तथा विस्तृत दिशा–निर्देशों सहित Monitoring Mechanism दो माह में जारी कर दिया जाएगा।

56. **'मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना'** के अन्तर्गत मैं 65 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रख रहा हूँ। भारत सरकार से भी इसमें अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होगा।

57. अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय बजट में महिलाओं और बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण–2 योजना को नया रूप दिया गया है। मैं सदन को अवगत करवाना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 18 हजार 925 आँगनवाड़ी केन्द्रों में से केवल 2 हजार 138 आँगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में चलाये जा रहे हैं। इस दिशा में पहल करते हुए मैं 1,000 नये आँगनवाड़ी भवनों के निर्माण की घोषणा करता हूँ। भवन निर्माण भारत सरकार, राज्य सरकार और मनरेगा के परस्पर समन्वय से किया जाएगा व इस पर लगभग 70 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

58. वर्तमान में प्रदेश में चल रहे आँगनवाड़ी केन्द्रों में से 6 हजार 718 आँगनवाड़ी केन्द्रों को मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इन मॉडल केन्द्रों में सलाईड, स्विंग, ब्लू मॉडल बेबी टेबल, कुर्सी इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मैं शेष बचे 12 हजार 207 आँगनवाड़ी केन्द्रों को भी चरणबद्ध तरीके से मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्र बनाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 32 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, माता और बहनों के सम्मान में मैं इतना ही कहना चाहूँगाः–

नारी शक्ति है, सम्मान है,
नारी गौरव है, अभिमान है।
नारी ने ही यह रचा विधान है,
नारी को शत–शत प्रणाम है।।

59. वर्तमान में **'विधवा पुनर्विवाह योजना'** के अन्तर्गत पुनर्विवाह को प्रेरित करने के लिए 50 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रति दम्पति देने का प्रावधान है। मैं इस अनुदान राशि को बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

60. अनुसूचित जाति एवं जन–जाति वर्गों द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम से लिए गए कर्जों के लिए One Time Settlement योजना को उदार बनाया जाएगा एवं इसकी समय सीमा बढ़ाई जाएगी। अभी तक एक हजार से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। योजना की समय अवधि बढ़ने के फलस्वरूप 12 हजार से अधिक लोगों के लिए 12 करोड़ की ब्याज और जुर्माना राशि की settlement हो पाएगी। Himachal Backward Classes Financial Development Corporation के ऋणियों के लिए भी One Time Settlement Scheme बनाई जाएगी।

61. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विभिन्न संस्थान जैसे बाल देखभाल संस्थान, जिला बाल संरक्षण इकाईयां, वृद्ध आश्रम आदि चला रहा है। इन सभी संस्थानों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय में एकरुपता लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से Top-up का प्रावधान किया जाएगा। यह Top-up तब तक मिलेगा जब तक कि भारत सरकार इन दरों में संशोधन नहीं करती।

62. **'मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना'** के अन्तर्गत प्रदेश के बाल–बालिका आश्रमों से निकले सभी ऐसे बच्चे जोकि आश्रम छोड़ने के बाद अपनी पढ़ाई जारी न रख पाए हों, को स्वरोज़गार के लिए 20 हजार रुपये देने का प्रावधान है। मैं इस अनुदान राशि को बढ़ाकर 35 हज़ार रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

63. मैं 2022–23 से राज्य के बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई **"मुख्यमन्त्री असहाय बाल पुनर्वास योजना"** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

न जाने वो बच्चा किस खिलौने से खेलता है,
जो दिन भर बाजार में खिलौने बेचता है।

64. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत लगभग 54 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 151 करोड़ रुपये की लागत से 26 विकास खण्डों में 119 जलागम विकास परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। इन्हें 2022-23 में आरम्भ कर दिया जाएगा। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

65. **'मनरेगा'** में **'पंचवटी'** योजना के तहत 28 वाटिकाओं का निर्माण किया जा चुका है तथा अन्य पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2022-23 में 200 अतिरिक्त वाटिकाओं व पार्कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

66. **'मनरेगा'** के तहत निजी और वन भूमि में वृक्षारोपण और बागवानी स्वीकार्य कार्य हैं। 2022-23 के दौरान वन विभाग के सहयोग से मनरेगा के तहत वृक्षारोपण पर 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

67. अध्यक्ष महोदय, धार्मिक एवम् पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों पर निरन्तर आवाजाही रहती है। इन सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालयों इत्यादि सहित 12 बहुउद्देशीय सुविधा केन्द्रों का convergence के माध्यम से प्रथम चरण में निर्माण किया जाएगा।

68. ग्रामीण क्षेत्रों में Solid and Liquid Waste Management हेतु प्लाज़मा तकनीक से चलने वाले प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण किया जाएगा। Plastic Solid Waste and Grey Liquid Waste Management के तहत 8 हजार गाँवों को लाया जाएगा। साथ ही सभी विकास खण्डों को क्रियाशील प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 870 ग्राम पंचायतों के प्रधानों सहित 2 हजार 510 कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

69. छठे राज्य वित्तायोग द्वारा की गई अनुशँसा के आधार पर मैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिबद्ध दायित्वों के भुगतान के लिए 352 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ जोकि 2021-22 से 104 करोड़ रुपये अधिक है।

70. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मैं सहर्ष निम्न घोषणा करता हूँः-

- अध्यक्ष, जिला परिषद को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 2,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- सदस्य, जिला परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- अध्यक्ष, पंचायत समिति को 2,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 1,500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- सदस्य, पंचायत समिति को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- प्रधान, ग्राम पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- उप–प्रधान, ग्राम पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- सदस्य, ग्राम पंचायत को 50 रुपये बढ़ौतरी के साथ 300 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 75 रुपये प्रति बैठक की वृद्धि की गई।

71. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अन्तर्गत कुल 32 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिससे लगभग 2 लाख 50 हजार से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। मैं यह घोषणा करता हूँ कि एक नई **“मुख्यमन्त्री महिला सशक्तिकरण योजना”** के अन्तर्गत इन महिला सहायता समूहों को निम्न अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगीः–

- उन सभी स्वयं सहायता समूहों को, जो कि ग्राम संगठन से जुड़े हैं, को Revolving Fund के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 25 हजार रुपये की One Time अतिरिक्त राशि Top-up के रूप में दी जाएगी। इससे इन समूहों को 25 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी।
- आगामी एक वर्ष के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तहत बने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ‘प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना’ व ‘प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के तहत शामिल किया जाएगा व इन बीमा योजनाओं के वार्षिक

प्रीमियम क्रमशः 12 रुपये एवम् 330 रुपये का भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

- Community Resource Person के Cadre में कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को वर्तमान में अपने गृह खण्ड विकास क्षेत्र में कार्य करने पर प्रतिदिन 350 रुपये मानदेय दिया जाता है। मैं इस मानदेय को 500 रुपये प्रतिदिन करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।
- **'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन'** के अन्तर्गत श्रेणी–1 जिलों क्रमशः शिमला, मण्डी, काँगड़ा तथा ऊना में, समय पर किश्त का भुगतान करने की अवस्था में, भारत सरकार द्वारा ब्याज उपदान देने के बाद इन समूहों को अधिकतम 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। शेष 8 श्रेणी–2 जिलों में यह ब्याज दर 7 प्रतिशत रहती है। मैं घोषणा करता हूँ कि श्रेणी–2 के 8 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को भी श्रेणी–1 के 4 जिलों के समरूप 4 प्रतिशत की दर से ही ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ब्याज उपदान देने के बाद जो भी अतिरिक्त ब्याज देय होगा उसे प्रदेश सरकार द्वारा Interest Subvention के रूप में वहन किया जाएगा।

72. पिछले वर्ष प्रारम्भ की गई **'स्वर्ण जयंती SHG सहयोग योजना'** एक नए प्रारूप में इस वर्ष भी जारी रहेगी। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2022–23 में विभिन्न सहायता समूहों के लिए 65 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 2022–23 में 1 हजार 662 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

73. अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत शिमला में जनता की सुविधा के लिए 2022–23 में 160 करोड़ रुपये की लागत से 59 परियोजनायें तथा धर्मशाला में 166 करोड़ रुपये की लागत से 65 परियोजनायें पूरी की जाएंगी। शिमला में 104 करोड़ रुपये की लागत से तथा धर्मशाला में 165 करोड़ रुपये की लागत से नये कार्य आरम्भ किये जाएंगे। शहरी विकास

74. शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग के निर्माण के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जाता है जबकि स्थानीय निकायों को शेष 50 प्रतिशत भाग वहन करना होता है। मैं सरकारी अँशदान को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

75. कोविड–19 महामारी के दौरान शहरी युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए 2020 में **'मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी'** योजना आरम्भ की गई थी। इसकी लोकप्रियता के चलते मैं इस योजना को 2022–23 में कुछ संशोधनों सहित जारी रखने की घोषणा करता हूँ जिस पर 5 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत शहरी बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार की गारंटी, पात्रता एवम् अन्य शर्तों से सम्बन्धित, विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।

76. शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अटल श्रेष्ठ शहर योजना शुरु की है जिसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 3 नगर परिषदों और 3 नगर पंचायतों को **'अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार'** से सम्मानित किया जाता है। अब इस योजना का विस्तार नगर निगमों के लिए भी किया जाएगा।

77. Legacy Waste Sites को साफ करने के बाद इन स्थलों पर वृक्षारोपण एवं पौधारोपण करके इनका सौन्दर्यकरण करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी जिसके

अन्तर्गत इनको पार्क तथा पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

78. छठे राज्य वित्तायोग द्वारा की गई अनुशँसा के आधार पर मैं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिबद्ध दायित्वों के भुगतान के लिए 187 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ जोकि 2021–22 से 24 करोड़ रुपये अधिक है।

79. मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँः–

- महापौर, नगर निगम को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- उप–महापौर, नगर निगम को 1,500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- काउंसलर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- अध्यक्ष, नगर परिषद को 1,500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- पार्षद, नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,300 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- प्रधान, नगर पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- उप-प्रधान, नगर पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- सदस्य, नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

शहरी विकास के लिए 2022-23 में 713 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गुणात्मक शिक्षा

80. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में हुए विस्तार के बारे में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सी पुस्तकों तथा रिपोर्टों में वर्णन मिलता है।

मेरे पिछले अभिभाषणों में घोषित शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुये मैं निम्न 6 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की घोषणा करता हूँः–

सूत्र–I : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन

- शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत चरणबद्ध ढँग से सरकारी प्राथमिक पाठ्शालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षायें आरम्भ की गई हैं। इनका और विस्तार किया जाएगा।
- सभी राजकीय माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्शालाओं में मिश्रित मोड के माध्यम से Real Time Online Teaching आरम्भ की जाएगी। इससे लगभग 6 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
- राज्य की सभी पाठशालाओं में एक नई **"श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन"** योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाएगी तथा राज्य के शीर्ष तीन स्कूलों को नकद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करता हूँ। इसी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की तीन शीर्ष पाठ्शालाओं को भी नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

सूत्र–II : IT के माध्यम से गुणवत्ता सुधार

विगत दो वर्षों में प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मेरे द्वारा घोषित तीन योजनायें अपने उद्देश्य में सफल होती दिख रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्न प्रस्तावित है : (1) 'स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय' जिसके अन्तर्गत 100 नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय, (2) 'स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय' जिसके अन्तर्गत 68 नये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा (3) 'स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट महाविद्यालय' – जिसके अन्तर्गत 10 नये राजकीय महाविद्यालय 2022–23 में सम्मिलित किये जाएंगे। मैं 2022–23 में इन तीनों योजनाओं को और अधिक बल देना चाहूँगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में IT की विशेष

भूमिका होगी। इन तीनों योजनाओं पर 54 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।

सूत्र–III : मेधा प्रोत्साहन

- वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जिनमें कई वर्षों से संशोधन नहीं हुआ है। इन सभी योजनाओं पर पुनर्विचार करते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि 'महर्षि बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना', 'इन्दिरा गान्धी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना', 'कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना', 'डॉ0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना' तथा 'स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना' जिनमें 700 रुपये से लेकर 1 हजार 250 रुपये तक का प्रावधान है, को बढ़ाकर 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह अर्थात् 18 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। 'राष्ट्रीय मिलिटरी कॉलेज छात्रवृत्ति योजना' तथा 'सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना' में यह राशि बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह अर्थात् 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान Armed Forces में शहीद अथवा विकलांग हुए जवानों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह आश्चर्य का विषय है कि इस छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 1983 से कोई भी वृद्धि नहीं हुई है तथा अभी तक छात्रों के लिए मात्र 30 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह का ही प्रावधान है। मैं इस विसंगति को दूर करते हुए इस योजना में भी उपरोक्त वर्णित योजनाओं के समरूप वृद्धि करते हुए 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह अर्थात् 18 हजार रुपये प्रतिवर्ष करता हूँ।
- इसके अतिरिक्त मैं IRDP छात्रवृत्ति योजना, जिसमें वर्ष 1991 से कोई वृद्धि नही हुई है को पुनर्नामित करते हुए एक नई **"मुख्यमन्त्री विद्यार्थी कल्याण योजना"**

करने की घोषणा करता हूँ तथा इनमें वृद्धि भी प्रस्तावित करता हूँ। मैं छात्रों के लिए इसे 300 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष करता हूँ। महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए इसे 1 हजार 200 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति वर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2 हजार 400 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा।

- मैं कक्षा 3 के 50 मेधावी छात्रों के लिए एक नई **"बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना"** शुरु करने की घोषणा करता हूँ। मेरिट के आधार पर चौथी और पाँचवीं कक्षाओं तक 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

- इन सभी योजनाओं में वृद्धि से 30 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इन सभी योजनाओं पर 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

- राजकीय विश्वविद्यालयों में शोध छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी स्त्रोत से कोई फेलोशिप प्राप्त नहीं होती। आर्थिक कारणों से ऐसे विद्यार्थियों को शोध कार्य करने में कोई बाधा न आए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं 2022-23 से एक नई **'मुख्यमन्त्री शोध प्रोत्साहन योजना'** के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की तिथि से शोध के प्रारम्भिक तीन वर्षों तक शोधार्थी को 3 हजार रुपये प्रतिमाह फेलोशिप देने की घोषणा करता हूँ। यह योजना शोध के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों के लिए न केवल सहायक होगी बल्कि साथ ही उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगी।

सूत्र–IV : समाज एवम् अभिभावकों की भागीदारी

- राज्य की शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु छात्रों के अभिभावकों तथा शिक्षकों के बीच एक वर्ष में कम से कम 3 दिन संवाद अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

सूत्र–V : पर्यावरण एवम् प्रकृति से परिचय

- सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2022–23 में 50 राजकीय महाविद्यालयों, 50 पाठ्शालाओं और 20 ITIs में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम स्थापित किये जाएंगे।

- वन विभाग तथा आयुष विभाग के सहयोग से 2022–23 में 200 राजकीय विद्यालयों तथा 50 राजकीय महाविद्यालयों में आयुष वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी जिनमें दुर्लभ औषधीय पौधों तथा जड़ी–बूटियों का रोपण किया जाएगा।

सूत्र–VI : रोज़गार परामर्श

- छात्रों के मार्गदर्शन तथा Career परामर्श की दृष्टि से सभी उच्च एवम् वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किये जाएंगे। इसके साथ ही रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राजकीय महाविद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में Career Guidance and Placement Cell की स्थापना की जाएगी और जहाँ ये पहले से विद्यमान हैं उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगाः–

किताब और कलम हर बच्चे की तकदीर बदलेगी,
ज्ञान की ज्योति हिमाचल की तस्वीर बदलेगी।

81. अध्यक्ष महोदय, शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वर्ष 1970 में स्थापित हुआ था। विगत् 52 वर्षों में प्रदेश के लिए यह एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय था। मैं घोषणा करता हूँ कि मण्डी में बन रहा 'सरदार पटेल विश्वविद्यालय' अप्रैल 2022 से कार्य करना आरम्भ कर देगा।

82. अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं और इनमें से कुछ संवर्गों के service matters लम्बे समय से लम्बित हैं। पिछले बजट में मैंने उन्हें सुलझाने की बात की थी। इस सन्दर्भ मैं यह कहना चाहूँगा कि :–

- B.Ed तथा TET योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम TGT (संस्कृत) तथा TGT (हिन्दी) किया जाएगा।
- प्रवक्ता (School Cadre) तथा प्रवक्ता (School New) श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता (School) किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त TGTs से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों को मुख्याध्यापक बनने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र के लिए 2022–23 में 8 हजार 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

83. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सुन्दरनगर स्थित जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आगामी सत्र से कम्प्यूटर साईंस में B.Tech तथा सिविल इंजीनियरिंग में M.Tech प्रोग्राम आरम्भ किये जाएंगे। कण्डाघाट स्थित राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान में इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग व राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, तलवाड़ में फार्मेसी के डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किये जाएंगे।

84. प्रदेश में चार नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नामतः लाडाघाट, श्री नैनादेवी जी, जिला बिलासपुर एवं कटौला, जिला मण्डी तथा धारटीधार और बेचर–का–बाग सिरमौर जिला में खोलने हेतु DPRs बनाई जाएंगी।

85. मैं प्लम्बिंग, वैल्डिंग, इलैक्ट्रीशियन तथा फ्रिज एवम् AC मुरम्मत जैसी सेवाओं को प्रदेश की जनता को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक नई **"कौशल आपके द्वार"** योजना आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जिन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यह ट्रेड चल रहे हैं उनके माध्यम से इन संस्थानों के नजदीक रह रहे उपभोक्ताओं को यह सेवायें न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।

जिसमें कौशल होगा, वही कुशल होगा।
कौशल के दम पर ही, वह सफल होगा।।

स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं चिकित्सा शिक्षा

86. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उदार वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाये गए हैं। 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त हुए 419 करोड़ रुपये तथा 2022–23 में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध 848 करोड़ रुपये को मिलाकर 2022–23 के अन्त तक भारत सरकार के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग 1 हजार 267 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध होगी। मैं प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इस सहायता के लिए हृदय की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूँ।

87. आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना के पूरक के रूप में हमारी सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2019 से 'मुख्यमन्त्री हिमाचल हैल्थ केयर योजना–हिमकेयर' आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 2 लाख 40 हजार लाभार्थियों को 218 करोड़ रुपये की लागत से निःशुल्क चिकित्सा सेवायें प्रदान की गई हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि हिमकेयर कार्ड की नवीनीकरण अवधि

एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी जाएगी। 'हिमकेयर' में नए परिवारों का पंजीकरण जनवरी से मार्च माह में होता है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस योजना में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरा वर्ष होता रहेगा। इसके अतिरिक्त हिमकेयर के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया जाएगा।

८८. प्रदेश के दूर–दराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर–द्वार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं एक नई **"मुख्यमन्त्री मोबाइल क्लिनिक (M3C)"** योजना की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक चलाया जाएगा। इसमें बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध होंगे। इसमें एक डॉक्टर द्वारा अपनी टीम के साथ गाँवों में जाकर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसमें डॉक्टर एक पारिवारिक डॉक्टर की तरह कार्य करेगा। कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहने वाले लोगों के लिए यह योजना एक वरदान साबित होगी।

८९. हृदय रोगों से पीड़ित रोगियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत् IGMC तथा RPMC Tanda में उपलब्ध कैथ लैब की सुविधा के अतिरिक्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर तथा नाहन में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर कुल २० करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

९०. कैंसर के मरीजों की सुविधा हेतु RPMC Tanda में पैट स्कैन एवं ब्रेकी थैरेपी (Brachytherapy) तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में पैट स्कैन एवं MRI की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ। इस पर ६१ करोड़ रुपये व्यय होंगे।

९१. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में एक व्यापक स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र स्थापित किया जाएगा जहाँ दानकर्त्ताओं के दूध का संग्रहण करने एवं परीक्षण, संरक्षण तथा वितरण की व्यवस्था होगी जिससे उपचाराधीन नवजात शिशुओं को दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

92. 2022–23 में प्रत्येक स्वास्थ्य खण्ड में एक 'मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र' विकसित किया जाएगा जिसमें Indian Public Health Standards (IPHS) के मानकों वाली सुविधायें सुनिश्चित की जाएंगी।

93. इस समय प्रदेश में नेशनल एम्बुलेंस सेवाएं–108 के अन्तर्गत 198 एम्बुलैंस चलाई जा रही हैं। इनके Response time को कम करने के उद्देश्य से 50 नई एम्बुलेंसों का क्रय किया जाएगा जिस पर 15 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

पूरा और निःशुल्क इलाज़ मिले सबको,
यह था हमारा सपना।
आयुष्मान भारत, हिमकेयर से,
बना स्वस्थ्य हिमाचल अपना।।

94. स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ कॉडर की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक नये आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों क्रमशः नाहन, चम्बा, नेरचौक तथा हमीरपुर में फैकल्टी और अन्य श्रेणी के समुचित पद भरे जाएंगे।

95. कोविड के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा सराहनीय सेवाएं प्रदान की गईं। विगत वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों का व्यापक विस्तार हुआ है। उसको देखते हुए मैं यह घोषणा करता हूँ कि चिकित्सा अधिकारियों के 500 नये पद सृजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2022–23 में 2 हजार 752 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

96. 2022–23 में हमारी सरकार 100 आयुष औषधालयों को Wellness Centres के रूप में स्तरोन्नत करेगी। आयुष

97. माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से 'योग' ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग

दिवस घोषित किया है। हमारी सरकार योग के प्रचार एवम् प्रसार के लिए हमेशा ही प्रयासरत रही है। इसी श्रृंखला में आयुष विभाग द्वारा Aayush Wellness Centres में महिला एवम् पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाये जाएंगे।

ऊर्जा/बहुउद्देशीय परियोजनाएं

98. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर दिये जा रहे अनुदान को अग्रिम रूप से बिजली बोर्ड को अदा कर रही है जिस पर हमारी सरकार अगले वर्ष 500 करोड़ रुपये उपदान प्रदान करेगी। हमारी सरकार 1 अप्रैल, 2022 से 4 लाख 40 हजार ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं, जिनकी मासिक बिजली खपत 60 युनिट तक है, उन्हें जीरो बिलिंग की जाएगी। 61-125 युनिट तक खपत करने वाले 7 लाख उपभोक्ताओं को 1 रुपये प्रति युनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए बिजली की दर 50 पैसे प्रति युनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति युनिट किया जाएगा। इन रियायतों से बिजली उपभोक्ताओं को वार्षिक 100 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

99. हमारी सरकार प्रदेश में 24 x 7 विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार 12 अतिरिक्त HT योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक अतिरिक्त HT योजना को 2022-23 में शुरु किया जाएगा। बढ़ते लोड को देखते हुए मौजूदा प्रणाली में 393 MV क्षमता की वृद्धि की जाएगी जिससे वोल्टेज़ की समस्या कम होगी।

100. कम वोल्टेज की समस्या को समाप्त करने के लिए 33/11 KV HT केन्द्रों के निर्माण तथा मौजूदा 33/11 KV HT केन्द्रों की क्षमता के विस्तार हेतु 2022-23 में 23 नई योजनाएं शुरु की जाएंगी जिससे सम्बन्धित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।

101. 'मुख्यमन्त्री रोशनी योजना' के अन्तर्गत पात्र 12 हजार 765 निर्धन परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। इस योजना के तहत 2022–23 में 5 हजार परिवारों को कनेक्शन दिये जाएंगे।

102. हमारी सरकार विद्युत वितरण नेटवर्क में मौजूद लकड़ी के खम्बों को सौ प्रतिशत बदलने हेतु प्रतिबद्ध है। 2022–23 में लगभग 20 हजार लकड़ी के खम्बों को लोहे के खम्बों से बदलकर इस कार्य को सम्पूर्ण कर लिया जाएगा।

कुछ नहीं होगा अन्धेरों को बुरा कहने से,
अपने हिस्से का दीया खुद ही जलाना होगा।

103. हाल ही में घोषित ऊर्जा नीति में राज्य को 2030 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर बल दिया गया है। मेरी सरकार ने बड़े पैमाने पर पम्प भण्डारण परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है।

104. 2022–23 में 1 हजार मैगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनायें जनता की सेवा में समर्पित कर दी जाएंगी। साथ ही साथ 4 नई विद्युत परियोजनाओं साई कोठी–1 (15 मैगावाट), देवी कोठी (16 मैगावाट), साई कोठी–II (16.5 मैगावाट) तथा हेल (18 मैगावाट) का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा। इन परियोजनाओं का निर्माण जर्मनी के Development Bank KfW की सहायता से होगा।

105. 2021–22 में HPPTCL ने लगभग 360 करोड़ की लागत से अनेक ट्रांसमिशन लाईनें विकसित की हैं। 2022–23 में HPPTCL ने 7 Extra High Voltage (EHV) सब स्टेशनों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 231 सर्किट किलोमीटर की कुल लम्बाई वाली 5 ट्रांसमिशन लाईनों तथा कुनिहार में संयुक्त नियन्त्रण केन्द्र के निर्माण को पूरा किया जाएगा। इन 13 परियोजनाओं पर 645 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

106. फ्रेंच विकास एजेंसी (AFD) ने चान्जू–III जल विद्युत परियोजना और दियोथल चान्जू जल विद्युत परियोजना

के वित्तपोषण के लिए सहमति दी है। AFD और भारत सरकार के बीच 800 करोड़ रुपये की राशि के क्रेडिट सुविधा समझौते (CFA) पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य 2022–23 में शुरु कर दिया जाएगा।

107. स्पिति में बिजली की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए बिजली बोर्ड तथा Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) के संयुक्त उद्यम द्वारा काजा में 1 MWh बैटरी भण्डारण प्रणाली सहित 2 MW क्षमता के सौर संयन्त्र की स्थापना की जा रही है जो 2022–23 में चालू कर दिया जाएगा।

108. Grid Connected Roof Top सौर ऊर्जा को आम जनता तक पहुँचाने के लिए तथा हरित ऊर्जा संकल्प हासिल करने हेतु मैं इन संयन्त्रों पर वर्तमान उपदान राशि को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति KW करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। यह उपदान राशि घरेलू उपभोक्ताओं को देय होगी।

109. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा की भी प्रदेश में बहुत सम्भावनाएं हैं, जिनका अभी समुचित दोहन नहीं हुआ है। SJVNL द्वारा 2022–23 में 600 करोड़ रुपये के निवेश से 150 MW क्षमता की सोलर परियोजनायें स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में इससे युवाओं को रोज़गार के नये अवसर प्राप्त होंगे व सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी यह एक अच्छी पहल होगी।

जल शक्ति

110. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूँगा कि 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत अब तक 8 लाख 35 हजार नल कनेक्शन दिये गये हैं। इसकी तुलना में पिछले 72 वर्षों में 7 लाख 63 हजार नल कनेक्शन दिये गए। हमारी सरकार की यह अभूतपूर्व उपलब्धि है। जनवरी, 2022 तक 17 लाख 28 हजार ग्रामीण परिवारों में से 15 लाख नवासी हजार परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान कर दिए

गए हैं। 2022 के अन्त तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। 2021–22 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्र का प्रथम राज्य है जिसे वर्ष 2021–22 में इस योजना की चौथी किश्त प्राप्त हुई है।

111. 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के बाद हमारी सरकार का लक्ष्य इन घरों को सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति करने का है। इसके लिए sensor आधारित तकनीक की सहायता से Real Time Basis पर पेयजल उपलब्धता तथा आपूर्ति की सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी।

सोचने से कहाँ मिलते हैं,
तमन्नाओं के शहर।
चलना भी जरूरी है,
मन्ज़िल पाने के लिए।।

112. अध्यक्ष महोदय, 2018–19 का बजट प्रस्तुत करते समय निर्मित Culturable Command Area (CCA) का केवल 45 प्रतिशत ही उपयोग हो पाता था। हमारी सरकार के सफल प्रयासों के चलते दिसम्बर, 2021 के अन्त तक लगभग 51 प्रतिशत CCA का उपयोग किया जाने लगा है। प्रदेश में विद्यमान सिंचाई योग्य 3.35 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से अब तक 1.87 लाख हैक्टेयर CCA का निर्माण किया जा चुका है। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के उद्देश्य से 2022–23 में 9 हजार हैक्टेयर CCA की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी तथा 6 हजार 500 हैक्टेयर CCA के लिए Command Area Development (CAD) किया जाएगा।

113. वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र की कार्य योजनायें 80 के दशक में बनाए गए मास्टर प्लान के अनुरूप कार्यान्वित की जा रही हैं। GIS के माध्यम से पूरे प्रदेश के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिससे कि किसान बन्धुओं को कम से कम समय में प्रभावी सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

114. 2022–23 के दौरान निम्न पाँच बड़ी पेयजल योजनाओं को जनता को समर्पित करने की घोषणा करता हूँः–

- 65 करोड़ रुपये की लागत से AIIMS बिलासपुर और हाईड्रो इंजीनियर कॉलेज के लिए कोल डैम उठाऊ पेयजल योजना।
- 110 करोड़ रुपये की लागत से टॉरखोला और अन्य गाँवों के लिए पेयजल योजना।
- 121 करोड़ रुपये की लागत से सिराज और बालीचौकी की 19 पंचायतों के लिए पेयजल संवर्धन योजना।
- 147 करोड़ रुपए से कमलाह व मण्डप के विभिन्न गाँवों के लिए पेयजल योजना।
- 56 करोड़ रुपये की लागत से डलहौजी के अन्तर्गत सलूणी, मन्जीर, सुनदाई इत्यादि क्षेत्रों में संवर्धन पेयजल योजनायें।

इन पाँच योजनाओं से लगभग 1 लाख 25 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

115. 2022–23 में ही निम्नलिखित 4 उठाऊ सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगाः–

- 6 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से भुन्तर में जरीब्राधा योजना जिससे 256 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी।
- 9 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से कुल्लू की ग्राम पंचायत बंदरोल के गिन्डौर, बनोगी, बबेली और सारी ग्राम समूहों हेतु योजना जिससे 417 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी।
- जिला कुल्लू में ही 2 करोड़ 31 लाख रुपये की लागत से रेरी मशगन योजना जिससे 93 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी।
- ग्राम पंचायत, सिकवारी के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत की योजना जिससे 120 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी।

116. 2022–23 में निम्नलिखित मल निकासी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगाः–

- 20 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से काला अम्ब के लिए मल निकासी योजना।
- 14 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से त्रिलोकपुर–खैरी के लिए मल निकासी योजना।
- 13 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से परवाणु जोन–I के लिए मल निकासी योजना।
- 4 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से ठियोग क्षेत्र के लिए मल निकासी योजना।
- 2 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से कोटखाई क्षेत्र के लिए मल निकासी योजना।
- 2 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से मैहतपुर के लिए मल निकासी योजना।
- 2 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से सुन्नी के लिए मल निकासी योजना।

117. 2022–23 के दौरान एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी जिसमें भारत सरकार के Uniform Drinking Water Quality Monitoring Protocol के अनुसार लगभग 70 प्रकार के परीक्षण करने की सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, पानी का कुशल प्रबन्ध ही लम्बे समय तक इसकी उपलब्धता को बनाये रख सकता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा किः–

पानी हूँ, जल हूँ, नीर हूँ मैं,
मुझे यूँ न व्यर्थ बहाया करो।
बन पड़े जितना भी तुमसे,
मुझे उतना ही तुम बचाया करो।।

जलशक्ति विभाग के लिए 2022–23 में 2 हजार 772 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़कें एवं पुल

118. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में लगभग 39 हजार किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य सड़कें हैं जिसमें से लगभग 32 हजार किलोमीटर लम्बी पक्की सड़कें हैं। गत् वर्ष पंचायतों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर 3 हजार 615 हो गई है। इनमें से 3 हजार 556 पंचायतें सड़क के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। शेष बची हुई 59 पंचायतों में से 20 पंचायतों को 2022–23 में सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

119. 2022–23 में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 1 हजार 500 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई जाएंगी जिनमें से 300 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें तथा 1 हजार 200 किलोमीटर लम्बी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 पुलों का निर्माण किया जाएगा। 315 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज की जाएगी तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना–III के अन्तर्गत 440 किलोमीटर लम्बी 45 सड़कों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। इन 45 सड़कों की कुल लागत 552 करोड़ रुपये है। जून, 2023 तक शेष बची DPRs भी भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जाएंगी।

120. वर्तमान में प्रदेश में कुल 2 हजार 592 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं। इनमें से 1 हजार 238 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग लोक निर्माण विभाग के पास हैं। 2022–23 में periodical रख–रखाव कार्यक्रम के अन्तर्गत 110 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर काम किया जाएगा जिसकी लागत लगभग 700 करोड़ रुपये होगी।

121. 2022–23 में नाबार्ड के RIDF के अन्तर्गत पोषित 180 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें, 235 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 395 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने तथा 25 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

122. 2022–23 में लगभग 60 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटस को सुरक्षित किये जाने का

लक्ष्य है ताकि इन चिन्हित स्थानों पर दुर्घटनाओं की सम्भावना को न्यूनतम किया जा सके।

123. अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली में बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव का समय आ गया है। 2022–23 में निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित हैंः–

- मैं महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के periodical रख–रखाव की सीमा को 5 एवं 6 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने की घोषणा करता हूँ ताकि अधिक से अधिक पर्यटक इन स्थलों पर भ्रमण का आनंद ले सकें। इस पर 350 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।
- Defect Liability Period के बाद रख–रखाव के बजट का कम से कम 20 प्रतिशत भाग सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
- मैं घोषणा करता हूँ कि सड़कों की मुरम्मत अथवा उन्नयन के समय, जहाँ पर भी सड़कों को उखाड़कर दोबारा से बिछाने की आवश्यकता हो, को आधुनिकतम तकनीक से उखाड़ा जाएगा। उखाड़ी गई सामग्री को re-cycle करके उसे उपयोग में लाया जाएगा ताकि कम समय तथा कम लागत में यह कार्य किया जा सके।
- सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु Geo-synthetic material technique का इस्तेमाल किया जाएगा।
- बर्फबारी के दौरान वाहनों को फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने के लिए एक नए अधिक प्रभावी पदार्थ Calcium Chloride Brine का इस्तेमाल किया जाएगा।
- ‘हिमाचल प्रदेश सड़क उन्नयन कार्यक्रम’ के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों में Cross Drainage और Culverts का प्रावधान किया जाएगा।

124. अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों के आधार पर पिछली सरकार और हमारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में निर्मित सड़कों की तुलना करना चाहता हूँ। हमारी सरकार के प्रथम चार वर्षों में ही पिछली सरकार के पाँच वर्षों में निर्मित जीप योग्य सड़कें 33 किलोमीटर अधिक हैं, मोटर योग्य सड़कें 660 किलोमीटर अधिक हैं, पक्की सड़कें 1 हजार 8 किलोमीटर अधिक हैं तथा 13 पुल अधिक हैं। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त क्रम को जारी रखते हुए 2022–23 में सड़कों एवम् उनसे सम्बन्धित सभी गतिविधियों के माध्यम से संक्षेप में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:–

- 1 हजार 60 किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण।
- 2 हजार 65 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को पक्का करना।
- 990 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर Cross Drainage
- 75 पुलों का निर्माण।
- 20 पंचायतों, 80 गाँवों तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य।
- 2 हजार 200 किलोमीटर लम्बी सड़कों की Periodical Maintenance

125. इन लक्ष्यों की पूर्ति से प्रदेश में वाहन योग्य सड़कों की लम्बाई 40 हजार किलोमीटर से अधिक तथा पक्की सड़कों की लम्बाई बढ़कर 34 हजार किलोमीटर हो जाएगी।

इस नदी की धार से ठण्डी हवा आती तो है,
इस अन्धेरे से इक सड़क उस भोर तक जाती तो है।

लोक निर्माण विभाग के लिए 2022–23 में 4 हजार 373 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उद्योग/ निजी निवेश

126. अध्यक्ष महोदय, 'मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना' रोज़गार सृजन की अब तक की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना बनकर उभरी है। इस योजना के अन्तर्गत 5 हजार से अधिक प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 457 करोड़ रुपये के निवेश से 2 हजार 800 उद्यमों में लगभग 8 हजार युवाओं को रोज़गार के अवसर मिले हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को तुरन्त भूमि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पायलट आधार पर जिला काँगड़ा में "मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन पार्क" स्थापित किया जाएगा जिसमें 250 वर्गमीटर तक के प्लाट व शैड विकसित किये जाएंगे।

127. अध्यक्ष महोदय, 'औद्योगिक निवेश नीति–2019' औद्योगिक विकास के लिए, विशेषकर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए, अनुकूल साबित हो रही है। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि यह नीति दिसम्बर, 2022 के स्थान पर दिसम्बर, 2025 तक जारी रहेगी।

128. 'मैडिकल डिवाइस पार्क' की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के पक्ष में की जा चुकी है। नालागढ़ स्थित इस पार्क को विकसित करने के लिए 2022–23 में कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इस पार्क के विकसित हो जाने से विदेशों पर निर्भरता कम होगी, प्रदेश में 5 हजार करोड़ का निवेश होगा जिससे 10 हजार लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस पार्क के विकास पर सरकार द्वारा 332 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

129. प्रदेश में रेशम उत्पादन की गतिविधियों से जुड़े लगभग 12 हजार किसान परिवारों की आय में वृद्धि के लिए Central Silk Board के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन Convergence के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

परिवहन

130. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र की सभी कर व्यवस्थाओं के सफल सरलीकरण के पश्चात् 2022–23 में इन करों का, पड़ोसी राज्यों के अनुरूप, युक्तिकरण किया जाएगा।

131. सड़कों पर वाहन एवम् यात्री सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से प्रत्येक RTO को एल्कोहल सेंसर, स्पीड राडार, Crash Investigation Lab तथा e-challan व्यवस्था से सुसज्जित Interceptor Electric वाहन उपलब्ध करवाये जाएंगे। इन वाहनों में उपस्थित अधिकारियों की सुविधा के लिए Body Worn Cameras भी उपलब्ध होंगे।

132. हमारी सरकार द्वारा ई–परिवहन व्यवस्था के माध्यम से परिवहन क्षेत्र में लर्नर लाईसेंस को छोड़कर लगभग हर सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करवाई जा रही है। 2022–23 में इस सुविधा को भी ई–परिवहन व्यवस्था में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

133. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सड़कों की पासिंग के लिए निर्धारित मापदण्डों की समीक्षा की जाएगी तथा छोटे चार पहिया वाहनों तथा छोटी बसों के लिए रोड पासिंग हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जाएंगे।

134. वर्तमान में एम्बुलैंस के पँजीकरण के लिए कोई दिशा–निर्देश नहीं हैं। सम्बन्धित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे जिससे कि एम्बुलैंस का भी पँजीकरण हो सके तथा मापदण्डों के आधार पर उनका भी सावधिक (periodic) रख–रखाव किया जा सके।

135. HRTC के बेड़े में अप्रैल माह तक 220 नई बसें सम्मिलित हो जाएंगी। 2022–23 में 200 नई बसें क्रय की जाएंगी जिनमें से 50 छोटी इलैक्ट्रिक बसें 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अन्तर्गत खरीदी जाएंगी।

मुश्किलें कितनी भी हों सामने हमारे,
हिम्मत हो तो रास्ता ज़रूर निकलता है।
जो खुद पे यकीन करके आगे बढ़ते हैं,
उनके साथ ही यह ज़माना चलता है।।

136. 2021–22 में 7 बस अड्डों का निर्माण पूरा करने के पश्चात् 2022–23 में 8 और बस अड्डों क्रमशः ठियोग, भंजराड़ू, बरछ्वाड़, हरिपुर देहरा, थुनाग, बंगाणा, नादौन तथा जंजैहली का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा।

137. मैंने पिछले बजट अभिभाषण में माननीय सदन को सूचित किया था कि नीति आयोग ने 'इलैक्ट्रिक वाहन नीति' बनाने के लिए प्रदेश को 'Light House State' के रूप में चयनित किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश सरकार द्वारा Electric Vehicle Policy-2021 को मंजूरी दे दी गई है। हमारी सरकार भारत सरकार के सहयोग से 'Electric Vehicles and Component Manufacturing' पार्क स्थापित करेगी।

138. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों से राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता से 2 हजार 95 करोड़ रुपये की नई परियोजना स्वीकृत करवाई है। यह परियोजना क्रमशः 1,000 करोड़ रुपये तथा लगभग 1 हजार 95 करोड़ रुपये के दो चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। इन दोनों चरणों के अन्तर्गत शहरों का सौंदर्यकरण, धरोहर भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन, हेलीपोर्ट का निर्माण, Eco-Tourism, Water Sports, Wellness Centers, Budhist Circuits, पर्यटन अधोसंरचना, युवाओं का प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित है। आगामी वित्त वर्ष में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार करके उनकी निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी। इनमें प्रमुख तौर पर कन्वेंशन सेंटर धर्मशाला, पालमपुर का सौंदर्यकरण, शिवधाम चरण–2, बाबा बालक नाथ मन्दिर का सौंदर्यकरण, वैलनेस सेंटर झटींगरी, कल्पा, रेणुका जी इत्यादि परियोजनायें शामिल हैं। पर्यटन

139. गत् 4 वर्षों में हमारी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बहुत से नये प्रयास किये हैं। मैं 2022–23 में निम्न कार्यों को पूरा करना प्रस्तावित करता हूँः–

- क्यारीघाट में कन्वेंशन सेंटर।

- टाउन हाल, शिमला में लाइट एण्ड साउंड शो।
- Food & Craft Institute (FCI) धर्मशाला का Institute of Hotel Management (IHM) के स्तर पर उन्नयन।

140. 2022–23 में 'नई राहें नई मंज़िलें' योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत मण्डी में शिव धाम, लारजी तथा तत्तापानी में वाटर स्पोर्टस, बीड़ बीलिंग में पैराग्लाईडिंग, चाँशल को विकसित करना सम्मिलित है।

141. अध्यक्ष महोदय, राज्य में अधिक से अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी से कुछ नये प्रयास किये जाएंगे जिनमें से निम्न प्रमुख हैंः–

- नये पर्यटन गंतव्यों पर जाने के लिए कारवां पर्यटन को प्रोत्साहन।
- पारम्परिक काठकुनी शैली की वास्तुकला वाले स्थानों को विभिन्न पर्यटन सर्किटों से जोड़ना।
- काँगड़ा जिले में आर्ट गैलरी को पर्यटन सर्किट से जोड़ना।
- ऐतिहासिक विरासत को प्रसारित एवं प्रचारित करने के लिए प्रदेश के ऐतिहासिक किलों को पर्यटकों के आकर्षण के रूप में विकसित करना।
- माउंटेन बाइकिंग ट्रैक शुरु करना।

142. 2022–23 के दौरान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए 'Interest Subvention' योजना जारी रखी जाएगी।

सबकी तकदीर बदलनी है, राह दिखानी है तुझे।
हाथों की लकीरों तक नहीं, उनसे आगे जाना है तुझे।।

वन संरक्षण एवं वनों से रोज़गार

143. अध्यक्ष महोदय, सतत् विकास लक्ष्य के अन्तर्गत 2030 तक राज्य के 30 प्रतिशत क्षेत्र को वन आवरण के

अधीन लाया जाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2022–23 में 15 हजार हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा।

144. Eco-Tourism को बढ़ावा देने के लिए फूलों और हिमालयी वनस्पतियों पर आधारित 20 Nature Trails विकसित किये जाएंगे।

145. जँगलों में भूमि कटाव रोकने और नमी को बढ़ाने हेतु 25 करोड़ रुपये की लागत से 125 स्थानों पर बाँध निर्माण किया जा रहा है। 2022–23 में जलाशयों के आस–पास के क्षेत्र को Eco-Tourism की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

146. चीड़ के जँगलों से स्थानीय समुदाय को बहुत सीमित आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। समुदायों के सहयोग से 2022–23 में 50 हैक्टेयर क्षेत्र में चीड़ के पेड़ों के स्थान पर चौड़ी पत्ती वाले पौधे रोपित किये जाएंगे। इससे पशुओं के लिए चारा मिलेगा, जँगलों में लगने वाली आग की घटनायें कम होंगी तथा भूमि कटाव रोकने में भी सहायता मिलेगी।

147. वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही तीन बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाएंगेः–

- 6 जिलों क्रमशः बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल–स्पिति, मण्डी तथा शिमला के 260 ग्राम पंचायत वार्डों में 50 करोड़ की लागत से आजीविका सृजन तथा अन्य विकास गतिविधियां की जाएंगी।
- 100 करोड़ रुपये की लागत से 428 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवम् प्रबन्धन परियोजनायें चलाई जाएंगी।
- काँगड़ा और चम्बा जिलों में 40 करोड़ रुपये की लागत से 150 Water Recharge Zones का Springshed Approach के अन्तर्गत उपचार तथा Cut Root Stock (CRS) विधि के माध्यम से

500 हैक्टेयर क्षेत्र में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया जाएगा और उस भूमि पर उपयोगी प्रजातियों का रोपण किया जाएगा।

148. 2022–23 में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लगभग 63 लाख मानव दिवस सृजित किये जाएंगे जिस पर 200 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इसके लिए वृक्षारोपण, भू–संरक्षण, जल भण्डारण, पर्यावरण–पर्यटन जैसे कार्य किये जाएंगे।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

149. माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले वर्ष नवम्बर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (COP-26) में अपने सम्बोधन में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पाँच अमृत तत्व प्रस्तुत किए जिसमें गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 GW तक पहुँचाने व अक्षय ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को वर्ष 2030 तक पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश की शत–प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा एवं ग्रीन ऊर्जा से पूर्ण किया जाए। इससे एक ओर हिमाचल प्रदेश देश का पहला पूर्णतः Green State बन जाएगा वहीं दूसरी ओर इस प्रमाणन से राज्य में निर्मित उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए।

150. शिमला–सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग के लिए एक "Green-e-Mobility" कार्यक्रम का एक प्रस्ताव बाह्य द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत तैयार किया जाएगा। इसके अन्तर्गत परिवहन संचालन व्यवस्था, Charging Station Network तथा ई–बैटरियों की replacement का प्रावधान किया जाएगा।

151. प्लास्टिक कचरे के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रदेश में प्लास्टिक कचरे की Value Chain के प्रभावी प्रबन्धन हेतु Extended Producer Responsibility हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा।

152. मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि 2022–23 में जर्मनी सरकार की संस्था GIZ के सहयोग से वर्षा जल संग्रहण नीति बनाई जाएगी तथा एक हजार गरीब किसानों के लिए इस नीति पर आधारित Demonstration Model स्थापित किये जाएंगे।

153. 2022–23 में Geographical Indication Act–1999 के अन्तर्गत राज्य के उत्पादों जैसे लाल चावल, किन्नौरी सेब, मण्डी की सेपूबड़ी, हिमाचली टोपी, सिरमौरी लोईया, हिमाचली धाम, थाची (मण्डी) धातु शिल्प, हिमाचली वाद्य यन्त्रों तथा किन्नौरी आभूषणों के पँजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

154. राज्य में Integrated Solid Waste Management से सम्बन्धित प्रस्तावों को online स्वीकृति देने तथा आवेदनों की online monitoring के लिए एक आधुनिक पोर्टल की स्थापना की जाएगी।

155. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का एक–एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मण्डी तथा ऊना में स्थापित किया जाएगा ताकि बोर्ड प्रभावी ढंग से काम कर सके। शिमला और पांवटा साहिब स्थित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं में निरीक्षण एवम् परीक्षण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इनकी सम्बद्धता National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) के साथ सुनिश्चित की जाएगी।

156. 2022–23 में प्रदेश में स्थित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों पर 14 नये निगरानी केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जो कि नदियों के जल की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् Robert James Brown के कथन, जिसमें कि उन्होंने Green Growth के महत्व को बतलाया है, का वर्णन करना चाहूँगा जो कि चिंता और चिंतन का विषय हैः–

"भविष्य या तो हरा होगा या तो नहीं होगा"

डिजिटाईजेशन

157. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, वन संरक्षण, भू–सर्वेक्षण, कृषि एवं बागवानी, आपदा प्रबन्धन, खनन् इत्यादि क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग की असीमित सम्भावनाएं हैं। अतः मैं चार स्तम्भों क्रमशः सक्षम शासन, ड्रोन मेले और महोत्सव, सक्षम नीतिगत ढाँचा और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर आधारित एक नई **"Governance and Reforms Using Drones (GARUD)"** योजना आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

158. 2022–23 में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हिमाचल में 4 फ्लाईंग स्कूल स्थापित किये जाएंगे। सरकारी विभागों के साथ–साथ राज्य के युवा भी ड्रोन सम्बन्धित प्रशिक्षण पाकर रोज़गार के अवसर का लाभ उठा सकेंगे।

159. 2022–23 में Governance को और प्रभावी बनाने के लिए निम्न कदम उठाये जाएंगेः–

- हमीरपुर जिला में पायलट आधार पर आरम्भ किये गए 'स्वामित्व' कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे जिले का सर्वेक्षण समाप्त किया जाएगा तथा सभी आबादी देह क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को भू–स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
- e-District के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की संख्या को मौजूदा 96 से बढ़ाकर 150 किया जाएगा।
- प्रदेश के छात्रों की सुविधा के लिए एक डिजिटल लाईब्रेरी स्थापित की जाएगी जिसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए study material online उपलब्ध करवाया जाएगा।
- सरकारी योजनाओं में pilferage रोकने के लिए वाऊचर आधारित e-RUPI प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
- ट्रैकर्स को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Trekker Information Portal विकसित किया जाएगा।
- दस पर्यटन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सार्वजनिक स्थानों में WiFi हॉटस्पॉट स्थापित किये जाएंगे।

- Litigation Monitoring System (LMS) को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि सभी Court Cases की अद्यतन स्थिति को LMS पोर्टल के माध्यम से देखा जा सके।
- सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए Family Register Database को update किया जाएगा।
- राहत कोष से प्रदेश के असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने हेतु एक वेबसाइट और एक Mobile Application के माध्यम से राहत वितरण की वर्तमान प्रक्रिया को स्वचालित किया जाएगा।

160. मैं सरकारी योजनाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण की माँग को पूरा करने के लिए वर्तमान डेटा सेंटर को अपग्रेड करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 38 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उनका यही है दावा कि सूरज उन्हीं का है,
मेरी यह ज़िद है कि सबको एक ही धूप मिले।

161. अध्यक्ष महोदय, National Generic Document Registration System प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय बजट 2022-23 में घोषित One Nation-One Registration के अनुरूप इस प्रणाली को राजकोष एवम् भू-अभिलेखों के साथ integrate करके इसे और प्रभावी और सुदृढ़ बनाया जाएगा। भू-प्रशासन एवं आपदा प्रबन्धन

162. Geological Survey of India (GSI) की मदद से किन्नौर जिला में भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरु की जाएगी। तदोपरान्त अन्य संवेदनशील जिलों में भी यह प्रणाली चरणबद्ध तरीके से शुरु की जाएगी जिसके लिए विस्तृत योजना रिपोर्ट बनाकर वित्त पोषण हेतु National Disaster Management Authority को प्रेषित किया जाएगा।

163. भारत सरकार की 'आपदा मित्र योजना' के अन्तर्गत 1 हजार 500 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

राजस्व संसाधन

164. अध्यक्ष महोदय, कोविड–19 के कारण देश एवम् प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के कर राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रदेश सरकार के प्रयत्नों एवम् lockdown के खुलने के उपरान्त कर राजस्व में भी आशानुसार बढ़ौतरी हो रही है जो कि हर्ष का विषय है। 2022–23 में 9 हजार 282 करोड़ रुपये कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने की सम्भावना है। 2022–23 में कर राजस्व में 2021–22 के अनुमानों की अपेक्षा 15 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है जो कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में मददगार सिद्ध होगी।

कर एवं आबकारी

165. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नशे के दुष्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु तथा प्रवर्तन (enforcement) को सुदृढ़ करने के लिए आबकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा।

166. हिमाचल प्रदेश एकीकृत नशा निवारण एवम् ड्रग्स नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा नशा निवारण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों/निगमों एवम् संस्थाओं के समन्वय के लिए आबकारी विभाग में एक नशा निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

167. हमारी सरकार द्वारा घोषित 'टैक्स हॉट' की सफलता और लोकप्रियता के दृष्टिगत् मैं घोषणा करता हूँ कि GST एकत्रिकरण व्यवस्था को और सरल तथा सुदृढ़ बनाने के लिए एक GST प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

168. कर एवं आबकारी विभाग में करदाताओं की सुविधा हेतु IT पर आधारित एक समर्पित व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। इससे करदाताओं तथा व्यापारी वर्ग के लिए GST अनुपालना और सुविधाजनक हो जाएगी।

169. हाल ही में हुए अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनर्वृति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता

जाँच हेतु एक मोबाइल App आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस मोबाइल App के माध्यम से बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन करने से ही शराब के वैध स्रोत का पता चल सकेगा।

170. गौवँश सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर 1 रुपया का अतिरिक्त Cess लगाया जाएगा।

171. अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल के अनुभवों से सीख लेते हुए हमारी सरकार online रोज़गार मेले आयोजित करेगी। 2022–23 में 9 रोज़गार मेलों व 120 कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किये जाएंगे। इसके साथ रोज़गार कार्यालयों में registration की पूरी प्रक्रिया की digitization की जाएगी। श्रम एवं रोज़गार

172. अध्यक्ष महोदय, मैं अपराध का पता लगाने और इसकी रोकथाम के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड–एण्ड–कंट्रोल सेंटर (CCC) की स्थापना की घोषणा करता हूँ। इन केन्द्रों की सहायता से CCTV तथा Integrated Traffic Management System (ITMS) के माध्यम से प्रभावी निगरानी की जाएगी। यह केन्द्र अवैध खनन, शराब की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों पर रोक लगाने में सक्षम होंगे। इसके लिए 7 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। गृह/कानून व्यवस्था

173. साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय शिमला में केवल एकमात्र पुलिस स्टेशन है। मैं घोषणा करता हूँ कि धर्मशाला और मण्डी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे।

174. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने आपातकाल के दौरान मीसा, DIR, CrPC के अधीन राजनीतिक व सामाजिक कारणों से कारावास व पुलिस स्टेशनों में निरुद्ध रहे व्यक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना आरम्भ की है। इसके अन्तर्गत 1 से 15 दिनों तक कारावास व पुलिस स्टेशनों में निरुद्ध रहे व्यक्तियों को 8 हजार व 15 दिनों से अधिक समय

तक निरुद्ध रहे व्यक्तियों को 12 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस राशि को बढ़ाकर मैं क्रमशः 12 हजार रुपये तथा 20 हजार रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

175. पुलिस आवास, पुलिस चौकियों, पुलिस थाने और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों जैसे पुलिस प्रशिक्षण और राज्य आपदा रिस्पांस बल प्रतिष्ठानों में ढाँचागत विकास और पूँजीगत कार्यों तथा आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध करवाने में गति दी जाएगी। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

176. प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में आग जैसी दुर्घटनाओं की स्थिति में तुरन्त राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मैं 2022–23 में 4 नये अग्निशमन केन्द्र खोलने और 5 अग्नि शमन पोस्टों को अग्निशमन उपकेन्द्र के रूप में उन्नयनित करने की घोषणा करता हूँ।

177. मैं गृह रक्षकों के लिए जिला और प्रदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता देने की घोषणा करता हूँ। साथ ही गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का Rank Allowance भी बढ़ाया जाएगा।

भाषा, कला एवं संस्कृति

178. अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने प्रदेश के विशिष्ट पहचान वाले 75 गाँवों का चयन किया है। इन गाँवों को देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना लागू की जाएगी। इससे इन गाँवों और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत पर्यटन की दृष्टि से भी देश और दुनिया के सामने आ सकेगी। इन गाँवों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशिष्टता को दर्शाने वाले लघु वृत्तचित्रों, पुस्तकों और अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा।

179. सरकार ने 2021 में सांस्कृतिक नीति की घोषणा की थी। इस नीति में घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रारम्भ में 2 करोड़ रुपये की राशि से सांस्कृतिक कोष गठित करने की मैं घोषणा करता हूँ।

180. स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि के रूप में मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में एक **"लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय"** की स्थापना की जाएगी।

181. स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की पावन स्मृति में प्रदेश सरकार हिमाचली लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए, **''लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान''** प्रारम्भ करेगी जोकि प्रति वर्ष लोक गायन के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा।

182. शिमला के बैंटनी कैसल (Castle) के जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में है। इसे शीघ्र ही शिमला शहर के इतिहास, कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए विशिष्ट पर्यटन स्थल के रूप में जनता को समर्पित किया जाएगा।

183. बिलासपुर में गोबिन्द सागर के निर्माण के समय जो मन्दिर पानी में समा गए थे को पुनःस्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना तैयार की गई है। 1 हजार 400 करोड़ रुपये की इस परियोजना का प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भेजा जाएगा।

जब तक संस्कृति है तब तक आस है,
बिना संस्कृति के मानव का विनाश है।।

184. बहुउद्देशीय साँस्कृतिक केन्द्र, कुल्लू का निर्माण लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। ऊना के सांस्कृतिक केन्द्र का लोकार्पण भी कर दिया गया है। बिलासपुर, मण्डी और सोलन में इन केन्द्रों का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। ये सभी 2022-23 में पूरे कर लिए जाएंगे जिन पर लगभग 22 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। चम्बा व नाहन में बन रहे केन्द्रों के निर्माण कार्य को भी गति दी जाएगी।

185. प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मन्त्रालय के सहयोग से 100 करोड़ रुपये की लागत से स्पिति के ताबो में 'भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान' की

स्थापना की जाएगी। इसके लिए 7.87 हैक्टेयर भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। 2022–23 में इसका निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

युवा सेवाएं एवं खेल

186. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य खेल संस्थान की स्थापना करने की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के गठन की मैं घोषणा करता हूँ।

187. प्रदेश में त्रिस्तरीय खेल महाकुम्भ का आयोजन सांसदों और विधायकों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, एथेलेटिक्स, वालीबॉल, बास्केटबाल और कुश्ती खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा जो जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान में सहायक सिद्ध होगा।

188. मैं 2022–23 में निम्नलिखित Indoor तथा Outdoor खेल परिसरों के लोकार्पण की घोषणा करता हूँः–

- नूरपुर में pre-fabricated बहुउद्देशीय हॉल।
- जंजैहली में indoor स्टेडियम।
- सरकारी महाविद्यालय बंगाणा में बहुउद्देशीय हॉल।
- माजरा (सिरमौर) में Hockey Astroturf Field
- सरस्वती नगर में 8 Lane 400 Meter Synthetic Track
- 10 करोड़ रुपये की लागत से टाण्डाखोली, जिला काँगड़ा में प्रस्तावित इण्डोर स्टेडियम का निर्माण शुरु किया जाएगा।

इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

189. सरकार स्वैच्छिक युवा क्लबों और विशेष रूप से युवाओं के क्षमता निर्माण को और मजबूत करेगी। सर्वश्रेष्ठ तीन युवा मण्डलों को वार्षिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ युवक मण्डल घोषित कर पुरस्कृत किया जाएगा जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को 51 हजार रुपये, द्वितीय को 31 हजार रुपये

तथा तृतीय स्थान पाने वाले को 21 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

190. अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली खेल–कूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाईट मनी को मैं प्रदेश के अन्दर 120 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन तथा प्रदेश के बाहर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

जनजातीय विकास

191. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जनजाति वर्ग की एक बहुत बड़ी संख्या गैर–जनजातीय क्षेत्रों में रह रही है। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों से बाहर रह रहे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए उचित कार्य योजना तैयार की जाएगी।

192. भारत सरकार द्वारा 2022–23 में देश की उत्तरी सीमा के साथ लगते क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए Vibrant Villages Programme घोषित किया गया है। 2022–23 में प्रदेश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए उचित कार्ययोजना तैयार करके इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की जाएगी।

वैकल्पिक यातायात

193. अध्यक्ष महोदय, land locked पहाड़ी राज्य होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में सड़क के अलावा यातायात के बहुत सीमित विकल्प उपलब्ध हैं। हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से विगत् वर्षों में इस परिदृश्य को परिवर्तित करने का सशक्त प्रयास किया है। मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार का दिल की गहराईयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2022–23 के बजट में प्रदेश में निर्माणाधीन 3 रेल लाईनों क्रमशः भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी के लिए 1 हजार 868 करोड़ रुपये, नंगल तलवाड़ा रेल लाईन के लिए 335 करोड़ रुपये तथा बद्दी–चण्डीगढ़ रेल लाईन के लिए 450 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। इन प्रावधानों के माध्यम से इन रेल लाईनों के कार्यान्वयन को गति मिलेगी। हमारी सरकार राज्य अँशदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

194. हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पांवटा साहिब–जगाधरी रेल लाईन का सर्वेक्षण पूरा कर रेल मन्त्रालय द्वारा DPR तैयार की जाएगी। इसके साथ ही भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा ऊना–हमीरपुर नई रेल लाईन के निर्माण की लागत के अँशदान पर भी सहमति बनाई जाएगी।

195. केन्द्रीय सरकार के 2022–23 के बजट में घोषित 'पर्वतमाला–राष्ट्रीय रज्जू मार्ग विकास कार्यक्रम' योजना प्रदेश के लिए हितकारी सिद्ध होगी। योजना के अन्तर्गत रोपवेज़ को, निजी भागीदारी से सड़क मार्ग के विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है जिससे कि पर्यटन तथा दैनिक आवाजाही में सुविधा होगी। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 4 रज्जू मार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाएंगे। इस नई योजना के लिए मैं भारत सरकार का आभारी हूँ।

196. हमारी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप नाबार्ड तथा भारत सरकार ने प्रदेश में रज्जू मार्गों को नाबार्ड के Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) के माध्यम से ऋण देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश में रज्जू मार्ग बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी। निर्माणाधीन बगलामुखी रज्जू मार्ग का 2022–23 में लोकार्पण कर दिया जाएगा।

197. हमारी सरकार के निरन्तर प्रयासों के कारण ही सम्भव हो पाया है कि आखिरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बल्ह में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण को तकनीकी रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यह हवाई अड्डा, उपकरण और रात्रि लैंडिंग सुविधाओं के साथ, एयर बस 320 जैसे बड़े विमानों को उतारने में सक्षम होगा। इसके निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU हस्ताक्षरित करने के पश्चात् भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ कर दी जाएगी।

198. वैकल्पिक यातायात सुविधाओं के सृजन के लिए 2022–23 में 2 हजार करोड़ रुपये राज्य कोष से व्यय किये जाएंगे।

199. अध्यक्ष महोदय, मैंने 2020–21 के बजट अभिभाषण में 'स्वर्ण जयन्ती आश्रय' योजना आरम्भ करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र लम्बित आवेदकों को आवासीय सहायता देने की घोषणा की थी। हमारी सरकार की इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि गत 2 वर्षों में सभी श्रेणियों सहित 22 हजार लाभार्थियों को विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्ययों से सहायता प्रदान की जा चुकी है। इनमें जन–जातीय क्षेत्रों में तथा इनसे बाहर रह रहे जन–जातीय वर्ग के लाभार्थी भी सम्मिलित हैं। आवासीय सुविधायें

200. मैं पूर्व की घोषणा के अनुसरण में 2022–23 में कुल 12 हजार 769 लाभार्थियों को आवासीय सुविधायें प्रदान की जाएंगी। योजनावार लक्ष्य निम्न प्रकार से हैंः–

- ❖ 'मुख्यमन्त्री आवास योजना' के अन्तर्गत 1 हजार 533 आवास।
- ❖ 'प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण)' के अन्तर्गत 1 हजार 262 आवास।
- ❖ 'प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी)' के अन्तर्गत 2 हजार 346 आवास।
- ❖ 'स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना' के अन्तर्गत शेष बचे सभी 7 हजार 628 आवास।

ख्वाब देखे हैं, हौंसले भी जिंदा हैं।
हम वो हैं जिनसे, मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं।

201. हमारी सरकार ने हमेशा ही Functional पदों को भरने को प्राथमिकता दी है। आगामी वर्ष में भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर, नर्सें, रेडियोग्राफर, OT सहायक, Lab टैक्निशियन, Dental Hygienist, फार्मासिस्ट, MRI टैक्निशियन, ECG टैक्निशियन तथा अन्य टैक्निशियनों के पद आदि शामिल हैं, 780 आशा कार्यकर्त्ताओं के नए पद भरे जाएंगे साथ ही 437 पद आशा फैसिलीटेटर, 870 Community Health Officer के पद भी भरे जाए। राष्ट्रीय भर्तियां

स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 264 पद भरे जाएंगे। हमीरपुर, नाहन, चम्बा तथा नेरचौक में स्थित नये आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में समुचित फैकल्टी तथा अन्य श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।

202. इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में खाली functional पदों को भी सरकार भरेगी जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर तथा Multi Task Part Time Workers शामिल हैं, भरे जाएंगे। जिनमें शिक्षा विभाग में विभिन्न शिक्षकों की भर्ती, पुलिस आरक्षी भर्ती, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद जैसे लाईनमैन, जुनियर T-Mate इत्यादि, HRTC में ड्राईवर तथा कण्डक्टर इत्यादि की आवश्यक भर्तियां, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायत सचिव, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, विभिन्न विभागों में लिपिक, JOA (IT), तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर, रेशम विभाग के इंस्पेक्टर तथा विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आदि शामिल हैं। आगामी वर्ष में शिक्षा एवम् लोक निर्माण विभाग में अँशकालीन मल्टी टॉस्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। गृह रक्षकों की नई भर्ती कई वर्षों से नहीं हो रही है। आगामी वर्ष में गृह रक्षकों की आवश्यक भर्ती करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। 2022-23 में प्रदेश सरकार 30 हजार रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवायेगी।

कर्मचारी कल्याण

203. अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों का कल्याण हमेशा ही मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। मैं सरकारी आवासों के रख-रखाव एवं मुरम्मत के लिए 2022-23 में 37 करोड़ रुपये और सरकारी आवासों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

204. अटल पैंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की पैंशन योजना है जिसके तहत 5,000 रुपये तक की मासिक पैंशन 60 वर्ष के बाद, नागरिकों को अँशदान के हिसाब से मिलती है। इस समय प्रदेश में 'अटल पेंशन योजना' के अन्तर्गत 1 लाख से

अधिक लोग जुड़े हैं। योजना के तहत श्रमिक, गृहिणी, व्यापारी वर्ग, किसान, बागवान और स्वरोजगारी युवाओं के लिए प्रदेश सरकार 2021–22 में 15 करोड़ रुपये का सरकारी अँशदान उनकी पैंशन निधि के लिए प्रदान करेगी। सरकार इस समय योजना के तहत 2 हजार रुपये प्रति वर्ष तक का अँशदान प्रदान करती है।

205. हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विभागों से जुड़े सभी पैरा वर्करज़ को इस योजना से आगामी वर्ष में जोड़ा जाए। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मैं प्रदेश सरकार के अँशदान की मौजूदा सीमा को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति वर्ष करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। साथ ही वर्तमान और नये लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के तहत देय सरकारी अँशदान की समय सीमा को मैं 31–03–2023 तक बढ़ाने की भी मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ। इससे 1 लाख 50 हज़ार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा परिणामस्वरूप हमारा प्रदेश Universal सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

206. आउटसोर्स कर्मियों से सम्बन्धित शिकायतों को मेरी सरकार ने गम्भीरता से लिया है। मेरी बजट घोषणा के अनुरूप दिसम्बर माह में सरकार ने एक मॉडल टेंडर सभी विभागों से सांझा किया है। इस मॉडल टेंडर के अनुसार हर कर्मी को एक पे–स्लिप देना अनिवार्य कर दी गई है। इस पे–स्लिप में सर्विस प्रोवाईडर कर्मी को लिखित रूप से समस्त कटौतियों जैसे EPF इत्यादि एवम् कर्मी को प्राप्त होने वाले Net Wages को दिखाना होगा। श्रम विभाग इन दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। मेरे हर बजट में न्यूनतम दिहाड़ी में प्रभावी बढ़ौतरी हुई है जिसका सीधा लाभ आउटसोर्स कर्मियों को मिला है।

207. प्रदेश की विकास यात्रा में कर्मचारियों के साथ–साथ विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज़ का अतुलनीय योगदान है। कोरोना काल में इन्होंने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सेवायें दी हैं। हमारी सरकार इनके कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है एवम् विगत चार बजटों में इनके मानदेय में यथा सम्भव वृद्धि की है। आगामी वर्ष के लिए मेरा प्रस्ताव निम्नलिखित हैः–

- आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को 1,700 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 9,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 4,550 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मासिक 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 6,100 रुपये मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3,100 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 900 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 4,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,600 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- आशा वर्कर को 1,825 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 4,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3,700 रुपये की प्रतिमाह बढ़ौतरी की गई। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर को भारत सरकार का अँशदान तथा Incentives दिये जाने का भी प्रावधान है।
- सिलाई अध्यापिकाओं को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,950 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1,650 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- मिड–डे–मील वर्कर्ज़ को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,900 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान

कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- जल रक्षक को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,800 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- हाल ही में नियुक्त हुये जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,900 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- दिहाड़ीदारों को 50 रुपये बढ़ौतरी के साथ 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में न्यूनतम 140 रुपये प्रतिदिन अर्थात् 4,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- इसके साथ हमारी सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स कर्मियों की दिहाड़ी में न्यूनतम 4,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी हो जाएगी। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पंचायत चौकीदार को 900 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,350 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई। पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से सम्बन्धित एक स्पष्ट नीति बनाई जाएगी।
- राजस्व चौकीदार को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- राजस्व लम्बरदार को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित

करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1,700 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी। SMC शिक्षकों की सेवाओं को यथावत् रखा जाएगा। इन अध्यापकों की सेवाओं से सम्बन्धित नीति बनाने के बारे में भी विचार किया जाएगा।
- IT Teachers को 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- SPOs को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

हर एक का दर्द सीने में ले के चलते हैं,
सब के दामन को खुशियों से भरते हैं।
यही चाहते हैं न रहे कोई ज़रूरतमन्द,
दिन रात सब के सपनों को पूरा करते हैं।।

बजट अनुमान

208. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022–23 के लिए 51 हजार 365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

209. अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2021–22 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 37 हजार 312 करोड़ रुपये हैं। 2021–22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 37 हजार 34 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2021–22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 278 करोड़ रुपये का राजस्व surplus अनुमानित है।

210. वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्तियां 36 हजार 375 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 40 हजार 278 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 3 हजार 903 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9 हजार 602 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.98 प्रतिशत है।

211. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमानों में नए कर का प्रस्ताव नहीं है। मुझे विश्वास है

कि प्रभावी कर अनुपालन, भारत सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

212. 2022–23 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये में से, वेतन पर 26 रुपये, पैंशन पर 15 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण अदायगी पर 11 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये, जबकि शेष 29 रुपये पूँजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है।

213. कोरोना के बावजूद विकास की गति को बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को GDP के 3 प्रतिशत से अधिक ऋण लेने की अनुमति प्रदान की है। इस कारण से प्रदेश के Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस बारे संशोधन विधेयक इसी सत्र में सदन में लाया जाएगा। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

वक्त की हलचल से घबराते नहीं हम,
हमारे हौंसले मुश्किलों में पलते हैं।
रुकते नहीं हम बाधाओं को देख कर,
हम वो चिराग हैं जो आँधियों में जलते हैं।।

214. अध्यक्ष महोदय, इस बजट के मुख्य बिन्दु संलगित अनुबन्ध में निहित हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी विनम्रता से इस सदन का आभार व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूँगा कि मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल का 5वां एवम् अन्तिम बजट प्रस्तुत किया है। मेरे लिए यह अत्यन्त गौरव और प्रसन्नता का विषय है तथा मैंने इस दौरान बहुत कुछ नया सीखा है।

हमारे लिए विगत् दो वर्ष अप्रत्याशित रूप से चुनौतीपूर्ण रहे क्योंकि इससे पूर्व किसी भी सरकार को महामारी और वैश्विक मन्दी का सामना एक साथ नहीं करना पड़ा। इस महामारी से जीवन के समस्त पहलू

प्रभावित रहे। हमें एक साथ सभी मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा।

इस कार्यकाल में वित्तीय बाधाओं का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए हमने सामाज के सभी वर्गों, विशेषकर उन वर्गों जिन्हें सरकार द्वारा सहायता की अधिक अपेक्षा होती है, की सेवा करने का प्रयास किया है। सामान्यतः पूर्व सरकारें समाज के ज़रूरतमन्द वर्गों के बारे में चुनाव के नज़दीक ही चिन्ता करना आरम्भ करती हैं किन्तु हमारी सरकार ने पहले बजट से ही सर्वजन कल्याण के लिए आवश्यक तथा प्रभावी कदम उठाये हैं।

मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट इस सदन में पहले प्रस्तुत बजटों से कहीं अधिक सम्पूर्ण एवम् समावेशी है। इस बजट में सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रणाली में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान महिलाओं में उद्यमित्ता प्रोत्साहित करने के लिए की गई घोषणाओं की ओर आकर्षित करता चाहूँगा। इस बजट में सभी कर्मचारी वर्गों एवं पैरा–वर्कर्ज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट महिला सशक्तिकरण तथा अनुसूचित जाति एवम् जनजाति वर्गों के कल्याण पर केन्द्रित है।

अध्यक्ष महोदय, जन कल्याण के साथ–साथ यह बजट विकासोन्मुखी भी है। इस बजट में पूँजीगत व्यय के माध्यम से बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण पर बल दिया गया है। मैं यह बजट प्रत्येक हिमाचल वासी के समृद्ध भविष्य के प्रति समर्पित करता हूँ।

जो रुक गया उसे क्या मुश्किलों से,
जो चलेगा उसी के पाँवों में छाला होगा।
औरों का दर्द होना चाहिए सीने में,
जो जलेगा उसी दीये से उज़ाला होगा।।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन को संस्तुत करना चाहूँगा।

जय हिन्द–जय हिमाचल

अनुबन्ध

सारॉंश

- 51 करोड़ 365 लाख रुपये का बजट आकार प्रस्तावित।
- 2021–22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान।
- निशुल्क एवम् सस्ती बिजली

बजट के प्रमुख बिन्दुः–

- ☞ **सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार**
- ☞ **बाल, महिला कल्याण एवम् सशक्तिकरण तथा अन्य वर्गों का कल्याण।**
- ☞ **शिक्षा में सुधार/छात्रवृत्तियों में बड़ी वृद्धि**
- ☞ **स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार**
- ☞ **किसानों/बागवानों की आय में वृद्धि**
- ☞ **रोजगाार एवम् कर्मचारी/श्रमिक कल्याण/पैरा वर्कर के मानदेय में सबसे बड़ी बढ़ौतरी।**
- ☞ **औद्योगिक विकास एवम् आधारभूत संरचना**
- ☞ **डिजीटाईजेशन**
- ☞ **प्राकृतिक संसाधन एवम् पर्यावरण**

1. सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार

- ✓ वृद्धावस्था पैंशन के लिए आयु सीमा सभी के लिए कम करके 60 वर्ष कर की गई।
- ✓ जो 850 रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 150 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ ऐसे वे वर्ग जो वर्तमान में 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की पैंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन का लाभ मिलेगा।

- ✓ 60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुषों को बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन का लाभ मिलेगा।
- ✓ 7 लाख 50 हजार से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ उठा पाएंगे जिस पर 1,300 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।
- ✓ अटल पैंशन योजना में सरकारी अँशदान को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया। मौजूदा 1 लाख लाभार्थियों की संख्या को 1 लाख 50 हज़ार तक लाने का लक्ष्य।

2. बाल, महिला कल्याण एवम् सशक्तिकरण तथा अन्य वर्गों का कल्याण

- ✓ बजट दस्तावेजों के साथ पहली बार Gender Budget Statement पेश की गई।
- ✓ 'गृहिणी सुविधा' तथा 'उज्ज्वला' योजनाओं में अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा जिस पर 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।
- ✓ 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के अन्तर्गत नई "मुख्यमन्त्री महिला सशक्तिकरण योजना" जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों को Revolving Fund में 25 हजार रुपये अतिरिक्त राशि Top-up में दी।
- ✓ प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- ✓ कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय।
- ✓ 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के अन्तर्गत श्रेणी–1 तथा श्रेणी–2 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को 4 प्रतिशत की समान दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ✓ मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को मिलने वाला अनुदान अब 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् दिव्यांगों को मिलने वाला अनुदान 30 प्रतिशत होगा।
- ✓ 'विधवा पुनर्विवाह योजना' में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपये की गई।
- ✓ बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई **"मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना"** प्रारम्भ की जाएगी।

- ✓ 'मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना' के अन्तर्गत अनुदान राशि बढ़ाकर 35 हज़ार रुपये की गई।
- ✓ बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान के लिए नई **"मुख्यमन्त्री असहाय बाल पुनर्वास योजना"** आरम्भ।
- ✓ 1,000 नये आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा।
- ✓ 12 हजार 207 आँगनवाड़ी केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा।
- ✓ SC/ST वर्गों द्वारा प्रदेश के SC/ST Development Corporation से लिए गए कर्जों के लिए One Time Settlement योजना की समय सीमा बढ़ाई जाएगी तथा उसे और अधिक उदार बनाया गया।
- ✓ Himachal Backward Classes Financial Development Corporation के ऋणियों के लिए उदार One Time Settlement Scheme.

3. शिक्षा में सुधार/छात्रवृत्तियों में बड़ी वृद्धि

- ✓ सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षायें आरम्भ होंगी।
- ✓ **"श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन"** योजना के अन्तर्गत शीर्ष स्कूलों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
- ✓ 'स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय' के अन्तर्गत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 'स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय' के अन्तर्गत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा 'स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट महाविद्यालय' के अन्तर्गत 10 नये राजकीय महाविद्यालय 2022–23 में सम्मिलित किये जाएंगे।
- ✓ 'महर्षि बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना', 'इन्दिरा गान्धी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना', 'कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना', 'डॉ0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना' तथा 'स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना' के अन्तर्गत अब 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे तथा 'राष्ट्रीय मिलिटरी कॉलेज छात्रवृत्ति योजना' तथा 'सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना' में यह राशि बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।
- ✓ Armed Forces में शहीद अथवा विकलांग हुए जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह होगी।
- ✓ **"मुख्यमन्त्री विद्यार्थी कल्याण योजना"** के अन्तर्गत छात्रों को 1 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाविद्यालयों में यह राशि 5 हजार रुपये प्रति वर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 6 हजार रुपये प्रति वर्ष होगी।

- ✓ कक्षा 3 के मेधावी छात्रों के लिए **“बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना”** आरम्भ होगी जिसके तहत 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देय होगी।
- ✓ शोधार्थियों के लिए **‘मुख्यमन्त्री शोध प्रोत्साहन योजना’** के अन्तर्गत 3 हजार रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दिया जाएगा।
- ✓ सभी उच्च एवम् वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किये जाएंगे।
- ✓ मण्डी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अप्रैल 2022 से कार्य आरम्भ होगा।
- ✓ जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आगामी सत्र से B.Tech कम्प्यूटर साईंस तथा सिविल इंजीनियरिंग के M.Tech प्रोग्राम आरम्भ किये जाएंगे।

4. स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार

- ✓ 2021–22 तथा 2022–23 में 1,267 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
- ✓ ‘हिमकेयर’ में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरे वर्ष होता रहेगा तथा इसकी नवीनीकरण अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी।
- ✓ दूर–दराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर–द्वार उपलब्ध करवाने हेतु **“मुख्यमन्त्री मोबाइल क्लिनिक (M3C)”** योजना आरम्भ होगी।
- ✓ RPMC Tanda में पैट स्कैन एवं Brachytherapy तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में पैट स्कैन एवं MRI की सुविधा।
- ✓ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में एक व्यापक स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र स्थापित होगा।
- ✓ प्रत्येक स्वास्थ्य खण्ड में एक ‘मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र’ विकसित किया जाएगा।
- ✓ 50 नई एम्बुलेंसों का क्रय किया जाएगा।
- ✓ चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ कॉडर की स्थापना की जाएगी।
- ✓ चिकित्सा अधिकारियों के 500 नये पद सृजित किए जाएंगे।
- ✓ सौ आयुष औषधालयों को Wellness Centres के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।
- ✓ योग के प्रचार एवम् प्रसार के लिए Aayush Wellness Centres में महिला एवम् पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाये जाएंगे।

5. किसानों/बागवानों की आय में वृद्धि

- ✓ प्रदेश में 11 स्थानों पर अनाज़ की खरीद शुरु होगी तथा 4 नई अनाज़ मण्डियों का निर्माण होगा।
- ✓ कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान।
- ✓ 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा।
- ✓ प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों का पंजीकरण होगा तथा श्रेष्ठ 50 हजार किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।
- ✓ कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवम् स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन होगा।
- ✓ स्वर्गीय श्री सत्यानन्द स्टोक्स की कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़ थानाधार व उसके आस–पास सत्यानन्द स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा।
- ✓ बागवानी क्षेत्र में 9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- ✓ 91 करोड़ रुपये की लागत से पराला मण्डी में फलों और सब्जियों के भण्डारण के लिए नया Cold Store स्थापित होगा।
- ✓ प्रदेश के 13 मार्केट यार्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा।
- ✓ प्रदेश में एक और फूल मण्डी स्थापित होगी।
- ✓ कृषि क्षेत्र में 20 और FPOs गठित किये जाएंगे।
- ✓ High Density किस्मों का पौधरोपण और इम्युनिटी बूस्टर वाली फसलों की शुरुआत की जाएगी।
- ✓ 'बागवानी विकास परियोजना' के अन्तर्गत शिलारु एवं पालमपुर में दो उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।
- ✓ प्रदेश में पाँच बड़ी Cow Sanctuaries एवम् गौ–सदनों की स्थापना होगी तथा गौवँश के लिए अनुदान अब 700 रुपये होगा। यह व्यवस्था अब **"गोपाल"** नाम से जानी जाएगी।
- ✓ दत्तनगर तथा चक्कर (मण्डी) में प्रतिदिन 50 हजार लीटर क्षमता के दो Milk Processing Plants शुरु होंगे।
- ✓ दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा।
- ✓ पशुपालकों के लिए 44 Mobile Veterinary Ambulances चलाई जाएंगी तथा 2 हजार भेड़ ईकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।

6. रोजगार एवम् कर्मचारी/श्रमिक कल्याण/पैरा वर्कर के मानदेय में सबसे बड़ी बढ़ौतरी

- ✓ 2022–23 में सरकार 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरेगी।
- ✓ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,000 रुपये मासिक मानदेय, मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये, आँगनवाड़ी सहायक को 4,600 रुपये, आशा वर्कर को 4,700 रुपये, पंचायत चौकीदार को 6,400 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7,850 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ को 3,400 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 3,800 रुपये, वाटर गार्ड को 4,400 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 5,400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। दिहाड़ीदारों को 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। राजस्व चौकीदार को 4,900 रुपये प्रतिमाह, राजस्व लम्बरदार को 3,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। IT Teachers के मानदेय में प्रतिमाह 1,000 रुपये तथा SPOs को 800 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी होगी। SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी। SMC शिक्षकों की सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा।
- ✓ B.Ed तथा TET योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम TGT (संस्कृत) तथा TGT (हिन्दी) किया जाएगा।
- ✓ प्रवक्ता (School Cadre) तथा प्रवक्ता (School New) श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता (School) किया जाएगा।
- ✓ इसके अतिरिक्त TGTs से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों को मुख्याध्यापक बनने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाएगा।
- ✓ पात्र ग्राम पंचायत Veterinary Assistants को फार्मासिस्ट के पद नियुक्त किया जाएगा।
- ✓ गृह रक्षकों के लिए जिला और प्रदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाएगा तथा गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का Rank Allowance भी बढ़ाया जाएगा।
- ✓ आऊटसोर्स कर्मियों के वेतन में 1,500 रुपये प्रति माह की बड़ी बढ़ौतरी।

7. औद्योगिक विकास एवम् आधारभूत संरचना

- ✓ भानुपल्ली–बिलासपुर, नंगल तलवाड़ा तथा चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाईनों के लिए 2,653 करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट। राज्य अंशदान प्रदान किया जाएगा।

- ✓ पांवटा साहिब–जगाधरी तथा ऊना–हमीरपुर रेल लाईनों के निर्माण की प्रक्रिया में गति।
- ✓ मण्डी ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU हस्ताक्षरित करने के बाद भू–अधिग्रहण शीघ्र शुरू किया जाएगा।
- ✓ पर्वतमाला–राष्ट्रीय रज्जूमार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 रज्जू मार्गों का निर्माण।
- ✓ 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत 2022 के अन्त तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। 2021–22 में 1,500 करोड़ रुपये का व्यय।
- ✓ 681 करोड़ की लागत से प्रदेश में पाँच बड़ी पेयजल योजनाओं, 4 उठाऊ सिंचाई योजनाओं तथा 7 मल निकासी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा।
- ✓ प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 300 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें, 1 हजार 200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 23 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर क्रॉस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
- ✓ 60 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटस को सुरक्षित किया जाएगा।
- ✓ सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु Geo-synthetic material technique का इस्तेमाल किया जाएगा।
- ✓ 'हिमाचल प्रदेश सड़क उन्नयन कार्यक्रम' के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों में Cross Drainage और Culverts का प्रावधान किया जाएगा।
- ✓ 1 हजार 60 किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 2 हजार 65 किलोमीटर लम्बी सड़कों को पक्का करना, 990 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर Cross Drainage, 75 पुलों का निर्माण, 20 पंचायतों, 80 गाँवों तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तथा 2 हजार 200 किलोमीटर लम्बी सड़कों की Periodical Maintenance.
- ✓ औद्योगिक निवेश नीति–2019 दिसम्बर, 2025 तक जारी रहेगी।
- ✓ 5 खेल परिसरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपये का व्यय।
- ✓ 3 बहु–उद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण 22 करोड़ रुपये से पूरा किया जाएगा।

- ✓ शिमला में 160 करोड़ रुपये से 59 तथा धर्मशाला में 166 करोड़ रुपये से 65 परियोजनाएं पूरी की जाएगी।
- ✓ Legacy Waste Sites को साफ करके इन स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ✓ 'मैडिकल डिवाइस पार्क' का निर्माण होगा जिससे 10 हजार लोगों को रोज़गार।
- ✓ 'Electric Vehicles and Component Manufacturing' पार्क स्थापित किया जाएगा।
- ✓ ADB के माध्यम से 2,095 करोड़ रुपये की पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना की स्वीकृति। दो चरणों में कार्यान्वयन किया जाएगा। 2022 में अधिकांश कार्यों की निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी।
- ✓ 'नई राहें नई मंज़िलें' योजना के अन्तर्गत मण्डी में शिव धाम, लारजी तथा तत्तापानी में वाटर स्पोर्टस, बीड़ बीलिंग में पैराग्लाईडिंग, चाँशल को विकसित किया जाएगा।
- ✓ 'Interest Subvention' योजना जारी रखी जाएगी।
- ✓ मुख्यमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत 1,533, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अर्न्तगत 1,262, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत 2,346 तथा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अन्तर्गत 7,628 आवासीय इकाईयों को मिलाकर विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 12 हजार 769 आवास।

८. डिजीटाईजेशन

- ✓ मैं चार स्तम्भों क्रमशः सक्षम शासन, ड्रोन मेले और महोत्सव, सक्षम नीतिगत ढाँचा और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर आधारित एक नई **"Governance and Reforms Using Drones (GARUD)"** योजना का शुभारंभ।
- ✓ ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हिमाचल में 4 फ्लाईंग स्कूल स्थापित किये जाएंगे।
- ✓ हमीरपुर जिला में पायलट आधार पर आरम्भ किये गए 'स्वामित्व' कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे जिले का सर्वेक्षण समाप्त किया जाएगा तथा आबादी–देह पात्र लाभार्थियों को भू–स्वामित्व निश्चित किया जाएगा।
- ✓ e-District के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की संख्या को 150 किया जाएगा।

- ✓ डिजिटल लाईब्रेरी स्थापित की जाएगी जिसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए study material online उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ✓ सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए Family Register Database को update किया जाएगा।

९. प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, प्रदूषण नियन्त्रण एवम् हरित राज्य

- ✓ प्रदेश की शत–प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा एवम् ग्रीन ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला Green State बनेगा।
- ✓ प्लाज़्मा तकनीक से चलने वाले एक प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण, Plastic Solid Waste and Grey Liquid Waste Management के तहत 8 हजार गाँव शामिल होंगे।
- ✓ बिजली उपभोक्ताओं को 60 युनिट तक जीरो बिलिंग, 61–125 युनिट तक 1 रुपये प्रति युनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति युनिट होगी।
- ✓ 'मुख्यमन्त्री रोशनी योजना' के अन्तर्गत 5 हजार परिवारों को कनेक्शन दिये जाएंगे।
- ✓ Grid Connected Roof Top सौर ऊर्जा अनुदान राशि 6 हजार रुपये प्रति KW होगी।
- ✓ वर्षा जल संग्रहण नीति बनाई जाएगी तथा एक हजार गरीब किसानों के लिए इस नीति पर आधारित Demonstration Model स्थापित किये जाएंगे।
- ✓ राज्य में Integrated Solid Waste Management से सम्बन्धित प्रस्तावों को online स्वीकृति देने का प्रावधान किया जाएगा।
- ✓ राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का एक–एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मण्डी तथा ऊना में स्थापित किया जाएगा।

10. अन्य

- ✓ नाबार्ड से अब 150 करोड़ रुपये की विधायक प्राथमिकता प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र पोषित होंगी जिसमें अब रोपवेज़ की योजनाओं को सम्मिलित किया जा सकेगा।
- ✓ 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' से माननीय विधायक शहीदों के सम्मान में 'द्वार' की अनुशंसा कर सकेंगे।

- ✓ 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' की राशि अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड़ रुपये होगी।
- ✓ 'विधायक ऐच्छिक निधि' को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया गया।
- ✓ प्रदेश में नशे के दुष्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु तथा प्रवर्तन (enforcement) को सुदृढ़ करने के लिए आबकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ✓ अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनर्वृत्ति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जाँच हेतु एक मोबाइल App आरम्भ की जाएगी।
- ✓ गौवँश सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर 1 रुपया का अतिरिक्त Cess लगाया जाएगा।
- ✓ 9 रोज़गार मेले व 120 कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किये जाएंगे। इसके साथ रोज़गार कार्यालयों में registration की पूरी प्रक्रिया की digitization की जाएगी।
- ✓ पंचायतों, जिला परिषद्, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद्, नगर परिषद्, और नगर पंचायतों के प्रधानों, उप–प्रधानों और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की गई है।
- ✓ अपराध की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड–एण्ड–कंट्रोल सेंटर (CCC) की स्थापना होगी।
- ✓ धर्मशाला और मण्डी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे।
- ✓ प्रदेश में 4 नये अग्निशमन केन्द्र खुलेंगे और 5 अग्नि शमन पोस्टों को अग्निशमन उप–केन्द्र के रूप में उन्नयनित किया जाएगा।
- ✓ स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में **"लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय"** की स्थापना की जाएगी।
- ✓ लोकगायन में उत्कृष्ठता के लिए 'लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान' की शुरूआत।
- ✓ खेल–कूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाईट मनी अब दोगुनी होगी।